

संक्षिप्त समाचार

वक्फ के अधिकारों पर लगाम लगाने की तैयारी

● मोदी सरकार ने कसी कमर ,नहीं चलेगी बोर्ड की ‘मजमानी’



नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड पर कंट्रोल करने की तैयारी कर रही है। उसकी किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने और उसकी अनियंत्रित शक्तियों पर अंकुश लगाना चाहती है। सुत्रों के मुताबिक, शुक्रवार शाम को कैबिनेट ने वक्फ अधिनियम में 40 से अधिक संशोधनों पर चर्चा की। इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने के लिए संशोधन भी शामिल है। आपको बता दें कि वक्फ बोर्ड के पास देशभर में लाखों करोड़ रुपये की संपत्तियां हैं।

वायनाड के तबाह घरों में अब हो रही चोरी

● अब तक 365 लोगों की हो गई मौत 206 लोग लापता



वायनाड (एजेंसी)। केरल के वायनाड में 29-30 जुलाई की रात भारी बारिश के बाद हुए लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 365 पहुंच गई है। इनमें 30 बच्चे शामिल हैं। 206 लोग अब भी लापता हैं। वायनाड लैंडस्लाइड में घर-जमीन खो चुके लोगों के पुनर्वास के लिए सरकार एक टाउनशिप बनाएगी। इधर एजेंसी के मुताबिक लैंडस्लाइड के बाद रिलीफ कैंप में रह रहे लोगों का कहना है कि उनके घरों में चोरियां हो रही हैं।

बिहार में तेजस्वी बढ़ाएं नीतिश-बीजेपी की टेंशन !

● 15 अगस्त के बाद करेंगे नई रणनीति पर काम शुरु



पटना (एजेंसी)। लोकसभा चुनाव 2024 में तेजस्वी यादव बिहार में एनडीए को सबक सिखाने की बात कर रहे थे लेकिन चुनाव परिणाम उनके मन-मुताबिक नहीं रहे। बिहार के लोगों ने राजद को लोकसभा की सिर्फ चार सीटें दीं। हालांकि ये बात और है कि राजद को बिहार में सबसे ज्यादा वोट मिला। अब तेजस्वी यादव 15 अगस्त के बाद बिहार में अपने पार्टी कार्यक्रमों में नया जोश भरने के लिए नई यात्रा की शुरुआत करने वाले हैं।

अब खत्म होगा इंतजार, ‘बुलेट’ ट्रेन दौड़ने को तैयार

नई दिल्ली (एजेंसी)। बुलेट ट्रेन का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने राज्यसभा में बताया कि बुलेट ट्रेन में 2 कैटेगरी होंगी, पहली सामान्य और दूसरी स्पेशल

● कहां तक पहुंचा काम,रेल मंत्री ने संसद में सब बताया

क्तास की। उच्च सदन में प्रश्नकाल के दौरान वैष्णव ने पूरक प्रश्नों के जवाब में यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बुलेट ट्रेन परियोजना पर काम तेजी से चल रहा है। उन्होंने कहा, ‘320 फिलर बनाने का काम पूरा हो गया है। समुद्र के नीचे करीब 50 मीटर गहरी सुरंग

रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा लैंगिक संवेदनशीलता और पेशेवर वातावरण में

भोपाल। रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय (आरएनटीयू) के विधि संस्थान, नर्सिंग विभाग, और महिला विकास प्रकोष्ठ द्वारा ‘लैंगिक संवेदनशीलता और पेशेवर वातावरण में महिलाओं की चुनौतियां’ पर केंद्रित एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य प्रतिभागियों को लैंगिक मुद्दों के प्रति जागरूक करना, भेदभाव और असमानता पर चर्चा करना और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए सहायक नीतियों और प्रथाओं को बढ़ावा देना था।

कार्यक्रम में बतौर अतिथि आईपीएस सुषमा सिंह, जम्मू विश्वविद्यालय में ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रोफेसर डॉ. रजनी डिंगरा, राज्य विधि महाविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. जीतेन्द्र गुप्ता, नेशनल ज्युडिशियल एकेडमी में रिसर्च फेलो डॉ. सोनम जैन, रबीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की प्रो. चांसलर डॉ. अदिति चतुर्वेदी, आरएनटीयू की कार्यवाहक कुलपति, डॉ. संगीता जौहरी उपस्थित रहे।

इस दौरान कार्यक्रम में डॉ. अदिति चतुर्वेदी ने उच्च शिक्षा की भूमिका को लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण बताया। आईपीएस

महिलाओं की चुनौतियां विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन



सुषमा सिंह ने कानून प्रवर्तन में महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की और प्रेरणादायक कहानियाँ साझा कीं। डॉ. रजनी डिंगरा ने लैंगिक संवेदनशीलता के मनोवैज्ञानिक और सामाजिक आयामों का पता लगाया और युवाओं को समुदाय में परिवर्तन के एजेंट बनने

के लिए प्रोत्साहित किया। डॉ. सोनम जैन ने कार्यस्थल में लैंगिक असमानताओं पर कानूनी ढांचे और न्यायिक दृष्टिकोण पर चर्चा की और आंतरिक शिकायत समितियों के कार्य और महत्व को विस्तार से बताया। डॉ. संगीता जौहरी ने विश्वविद्यालय की लैंगिक संवेदनशीलता के

प्रति प्रतिबद्धता का परिचय दिया। डॉ. जीतेन्द्र गुप्ता ने पेपर प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया और विषय पर अपने विचार साझा किए।

इससे पूर्व स्वागत सत्र में डॉ. निलेश शर्मा, डीन, विधि संस्थान, ने संगोष्ठी के विषय का परिचय दिया और सभी प्रतिष्ठित अतिथियों का स्वागत किया। डॉ. नैश ज़मीर, चेयरपर्सन, महिला विकास प्रकोष्ठ और प्रमुख, विधि संस्थान, ने महिला विकास प्रकोष्ठ की पहलों पर अपने विचार साझा किए।

कार्यक्रम में विधि संस्थान और नर्सिंग विभाग के सभी संकाय सदस्य और महिला विकास प्रकोष्ठ के सभी सदस्य राष्ट्रीय संगोष्ठी में उपस्थित रहे। संगोष्ठी में इंटरएक्टिव सेगमेंट, शिक्षाविदों, शोधार्थियों, और छात्रों द्वारा प्रस्तुतियां और सर्वश्रेष्ठ पेपर प्रस्तुतियों की पहचान शामिल रही। कुल 57 पेपर प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 15 को प्रस्तुति के लिए चुना गया। पीएचडी शोधार्थियों और स्नातक छात्रों के पेपर अलग-अलग मूल्यांकित किए गए।

ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सरकार ले आई है नए नियम

ट्रांसप्लांट के लिए मानव अंगों को भेजने और लाने को लेकर गाइडलाइन जारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। केंद्र सरकार ने ट्रांसप्लांट के लिए मानव अंगों को भेजने और लाने को लेकर पहली बार गाइडलाइन जारी की है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने हवाई, ट्रेन, रोड और शिपिंग रूट से ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन को लेकर शनिवार (3 अगस्त) को एसओपी जारी की। एयर रूट से ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन के दौरान

सकता है कि विमान में मानव अंगों को ले जाया जा रहा है। ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत तक पड़ती है, जब ऑर्गन डोनर और ऑर्गन रिसीवर, दोनों एक शहर के भीतर या अलग-अलग शहरों में अलग-अलग अस्पतालों में हों। तब एक जीवित



अंग को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि ऑर्गन ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस को व्यवस्थित करने के पीछे हमारा लक्ष्य कीमती अंगों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। ये एसओपी देश भर में ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन और अस्पतालों के लिए सही मानकों का पालन तय करने के

अदालती कार्यवाही से तंग आकर समझौता कर लेते हैं लोग

● खुद सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने ही खोल दी सिस्टम की पोल



नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि लोग अदालती कार्यवाही से इतने त्रस्त हो चुके हैं कि वे किसी तरह बस समझौता चाहते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायिक प्रक्रिया वादियों के लिए एक सजा हो गई है। लोग इससे छुटकारा पाने के लिए अक्सर कम समझौते को भी स्वीकार कर लेते हैं। सीजेआई चंद्रचूड़ ने लोक अदालतों की भूमिका और महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह (लोक अदालत) एक ऐसा मंच है, जहां अदालतों में या मुकदमेबाजी से पहले लंबित विवादों और मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से समझौता किया जाता है।

सपनि फिर शुरू करने की मांग को लेकर भाकपा का आन्दोलन 30 को

भोपाल। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पुनः शुरू करने की मांग को लेकर आगामी 30 अगस्त 2024 को राज्य व्यापी आन्दोलन किया जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के मध्य प्रदेश राज्य सचिव कॉमरेड अरविन्द श्रीवास्तव और राज्य सह सचिव कॉमरेड शैलेन्द्र शैली ने यहां जारी एक विज्ञप्ति में बताया कि मध्य प्रदेश में सड़क परिवहन निगम को बंद करके प्रदेश की जनता के साथ घनघोर अन्याय किया गया है। कांग्रेस और भाजपा के नेताओं की मिलीभगत से निजी क्षेत्र के परिवहन को लाभ पहुंचाने के लिए ही मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम को बंद किया गया। अब स्थिति इतनी बदतर है कि निजी बसों के मालिकों की मनमानी से जनता पर अत्याचार हो रहा है। खटारा बसों के कारण प्रायः दुर्घटनाएं हो रही हैं। त्रौहरो के अवसर पर बसों का क्रियायमानमना ढंग से बढ़ा दिया जाता है। बसों में जनता को जानवरों की तरह भर दिया जाता है और अपमानजनक दुर्व्यवहार किया जा रहा है। इस चिंताजनक स्थिति पर सरकार का कोई भी नियंत्रण नहीं है। भारत के अधिकांश राज्यों में सरकारी परिवहन निगम के माध्यम से जनता को परिवहन की बेहतर सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की जनता इससे वंचित है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पुनः शुरू करने की मांग को लेकर आगामी 30 अगस्त 2024 को राज्य व्यापी आन्दोलन किया जाएगा। इस अवसर पर सभी जिला मुख्यालयों पर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा मध्य प्रदेश सड़क परिवहन निगम पुनः शुरू करने की मांग को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के लिए ज्ञापन जिला कलेक्टर को सौंपा जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट ने मध्य प्रदेश की जनता से इस मांग को लेकर लामबंद होने का आह्वान किया है।

यूपी में मुश्किल में बीजेपी, दूर नहीं हो रही चिंता

नई दिल्ली (एजेंसी)। भाजपा में लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद देश के विभिन्न राज्यों से सामने आ रही नाराजगी से पार्टी नेतृत्व असहज है। खासकर उत्तर प्रदेश के हालात उसके लिए चिंता का विषय है, जहां राज्य के बड़े नेताओं के मतभेद कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी नाराजगी सामने आ रही है। कहीं सरकार के भीतर दिक्कतें हैं, तो कहीं सत्ता और संगठन में अजबन बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश को लेकर भाजपा नेतृत्व ने राज्य के नेताओं को आपसी मतभेदों को उजागर न करने और विधानसभा उप चुनाव के लिए एकजुट होकर तैयारी करने को कहा है।

ऋषिकेश से अंतिम संस्कार कर लौट रहा था परिवार

राजस्थान में सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत

सवाई माधोपुर (एजेंसी)। सवाई माधोपुर में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह 7 बजे एक कार ट्रक से टकरा गई। हादसे में भाई-बहन समेत 4 लोगों की मौके पर मौत हो गई। 6 लोग

● दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे पर हादसा, दो सगे भाई-बहन

घायल हो गए। हादसा सूरवाल थाना क्षेत्र के त्रिलोकपुरा गांव के पास हुआ। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया। सीओ सिटी हेमेंद्र शर्मा ने बताया- परिवार की एक महिला घुस गई। हादसे में मौनिका (24) पुत्री कार्यक्रम में गई थी, जहां उसकी मौत हो गई थी। मौत की सूचना के बाद परिजन ऋषिकेश पहुंचे। परिजन ने शव घर लाने के बजाय उसका अंतिम संस्कार ऋषिकेश में



ही किया। अंतिम संस्कार करने के बाद सभी परिजन घर लौट रहे थे। इसी दौरान ड्राइवर को झपकी आ गई। वह कार का ब्रेकस खो बैठा और कार पीछे से ट्रक में घुस गई। हादसे में मौनिका (24) पुत्री कचरूलाल प्रजापत, राजन (22) पुत्र कचरूलाल प्रजापत, रेखा (42) पत्नी ईश्वर लाल प्रजापत और धांपू देवी (65) पत्नी हीरालाल प्रजापत की मौत हो गई।

मौनिका और राजन भाई-बहन थे। धांपू देवी और रेखा मां-बेटी थे। शव जिला अस्पताल की मॉर्चरूम में रखवाए गए हैं। पायल (26) पत्नी कमलेश प्रजापत, कृष्णा (40) पत्नी कचरूलाल प्रजापत, बुलबुल (22) पुत्री कचरूलाल प्रजापत, ज्योति (37) पत्नी अर्जुन प्रजापत, अनिता (1) पुत्री अर्जुन और शकील खान (24) पुत्री नबी खान घायल हुए हैं।

आतंकियों पर लगाम के लिए ‘पुलिस-पब्लिक’ फॉर्मूला

जम्मू में पुलिस ने शुरू किया स्पेशल प्लान, दक्षिणी हिस्से से शुरुआत



जम्मू (एजेंसी)। जम्मू कश्मीर में हालिया दिनों में आतंकी घटनाओं में इजाफा हुआ है। अब इस पर लगाम लगाने के लिए स्पेशल प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत ‘पुलिस-पब्लिक’ फॉर्मूला आजमाया जा रहा है। जम्मू पुलिस ने आम नागरिकों के लिए इसका विवरण जारी कर दिया है। बता दें कि बीते दिनों में खासतौर पर जम्मू आतंकियों के निशाने पर रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल पर घुसपैठ की कोशिशें भी खूब हुई हैं। आतंकी हमलों में जम्मू में करीब 22 लोग मारे गए हैं, जिनमें 11 सुरक्षा जवान, एक गांव रक्षा गार्ड का सदस्य भी शामिल है। यह घटनाएं राजौरी, पुंछ, रियासी, ऊरमपुर, कठुआ और डोडा जिलों में हुई हैं। वहीं, पिछले महीने कठुआ और डोडा जिले में दो एनकाउंटर्स के दौरान पांच आतंकियों को भी मार गिराया गया।

संपादकीय

मुद्दा जल्द इंसाफ मिलने का है...

सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने भारतीय न्याय व्यवस्था की चिंताजनक खामी की ओर संजीवनी के साथ जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि लोग अदालतों के मामलों से इतने तंग आ चुके हैं कि वे बस समझौता चाहते हैं। लोक अदालतें ऐसे मंच हैं, जहां अदालतों में लंबित या मुकदमेबाजी से पहले के विवादों और मामलों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निपटारा या समझौता किया जाता है। उन्होंने कहा कि कोर्ट की इस तरह की प्रक्रिया ही एक सजा है, जो जजों के लिए चिंता का विषय है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने आगे कहा कि आपसी सहमति से हुए समझौते के खिलाफ कोई अपील दायर नहीं की जा सकती। प्रधान न्यायाधीश दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में विशेष लोक अदालतों के सत्र का शुभारंभ करते हुए बोल रहे थे। लोक अदालतों की उपयोगिता रेखांकित करते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि लोक अदालत के आयोजन में उन्हें हर स्तर पर बार और बेंच सहित सभी से अपार समर्थन और सहयोग मिला। जब लोक अदालत के लिए पैनल गठित किए गए थे तो यह सुनिश्चित किया गया था कि प्रत्येक पैनल में दो जज और बार के दो सदस्य शामिल होंगे। ऐसा करने के पीछे उद्देश्य अधिकवाओं को संस्था पर स्वाभिम्वल देना था, क्योंकि यह ऐसी संस्था नहीं है जो केवल न्यायाधीशों से चलाई जाती है और यह न्यायाधीशों की, न्यायाधीशों के लिए, न्यायाधीशों वाली संस्था नहीं है।वैश्विक प्रधान न्यायाधीश ने जो कहा वो भारतीय न्याय व्यवस्था की कड़वी सच्चाई है। क्योंकि लोग इंपाफ की आस में अदालत आते हैं, लेकिन वहीं न्याय मिलने में बरसों लग जाते हैं और देरी से मिला न्याय भी अन्याय जैसा ही है। इसाफ मिलने में देरी के कई कारण हैं। पहले तो हमारी न्याय प्रक्रिया काफी धुलमुल तरीके से काम करती है। सामान्य और काफी हद तक स्पष्ट मामलों में भी मुकदमें बरसों लटके रहते हैं। कोर्ट में तारीख पर तारीख लगती रहती है। न्याय दूर तक नजर नहीं आता। अगर निचली अदालत में फैसला हो भी जाए तो ऊपरी अदालतों में मामले सालों चलते रहते हैं। हाल में सरकार ने नई भारतीय न्याय संहिता में फौजदारी मामले के फैसले की एक समय सीमा तय की है। दीवानी मामलों में भी ऐसा करना जरूरी है। तारीख पर तारीख का सर्वाधिक लाभ वकील समुदाय को होता है, जिन्हें फीस मिलती रहती है। लेकिन मुवाकिलत कचहरी के धक्के खाता रहता है। कई लोग तो न्याय की आस में दुनिया भी छोड़ जाते हैं। लोगों का न्याय व्यवस्था पर विश्वास उठने के पीछे कई कारण हैं। पहला तो अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या। भारत दुनिया का ऐसा देश है, जहां कोर्ट में सबसे ज्यादा मुकदमे लंबित हैं। देश भी की अदालतों में 2024 में लंबित मुकदमों की संख्या 5.1 करोड़ थी। इनमें से भी 1 लाख 80 हजार मामले तो ऐसे हैं, जो 30 साल से पेंडिंग हैं। जल्दी फैसले न हो पाने के पीछे कारण जजों की कमी है। वर्तमान में प्रति 10 लाख आबादी पर 21 जज हैं,जबकि होना चाहिए 50 जज। जजों की कमी की वजह सरकार द्वारा न्यायधीशों की नियुक्ति में देरी करना है। सुप्रीम कोर्ट तक में जजों के पद खाली पड़े हैं। इस मुद्दे पर जजों की नियुक्ति करने वाले कॉलेजियम और सरकार के बीच मतभेद की खबरें भी आती रहती हैं। निचली अदालतों में प्रतिभाशाली लोग कम ही जज बनना चाहते हैं। यहां तक कि जजों को भी अपने वेतन भत्ते पाने के लिए ऊंची अदालतों का सहारा लेना पड़ता है। दूसरे, न्याय व्यवस्था पर सरकार अधेशा और जरूरत से काफी कम खर्च करती है। अदालतों में गैर न्यायिक स्टाफ की भी कमी है। ऐसे में लोग आपस में समझौता कर मामले न निपटाएं तो क्या करें?

नजरिया

रघु ठाकुर

लेखक समाजवादी विचारक हैं।



महाराष्ट्र कैडर की चयनित आई.ए.एस. सुश्री पूजा खेड़कर इस समय मीडिया में काफी स्थान पा रही हैं। उनके पिताजी भी आई.ए.एस. रहे हैं और जो सेवानिवृत्ति के बाद संसदीय चुनाव में प्रत्याशी भी रहे हैं। उनकी माँ अभी जेल में हैं और उनके प्लॉट खाली कराने के लिये पिस्टल लहखोते फेंगे सारे देश ने देख हैं। पूजा खेड़कर पहली बार चर्चा तब आयी जब वे प्रशिक्षु के तौर पर पूना में पदस्थ थीं और वहां के कलेक्टर जो छुट्टी पर गये थे। वे उनकी अनुपस्थिति में उनके कमरे और कुर्सी पर काबिज हो गई थी साथ ही उन्होंने कलेक्टर की नाम पटिटका हटाकर अपने नाम की पटिटका लगा ली थी। जबकि उनका प्रशिक्षण काल पूरा नहीं हुआ। कलेक्टर के लौटकर आने के बाद उन्हें इस घटना की जानकारी मिली और उन्होंने मुख्य सचिव को जानकारी दी, क्योंकि यह सिविल सर्विस काल के हिसाब से अनुशासनहीनता है। पूजा खेड़कर यहीं नहीं रुकी बल्कि जब उन्हें कलेक्टर के द्वारा की गई शिकायत की जानकारी मिली तो उन्होंने कलेक्टर को ही नोटिस दे दिया। उन्हें उनके प्रशिक्षण को पूरा करने के लिये मंजूरी जाने को कहा गया पर उन्होंने उस पर भी अवज्ञा की और सार्वजनिक रूप से अधिकारियों की आलोचना शुरू कर दी। स्वभाविक था कि, आईएएस लॉबी जो एक प्रकार से जाति का रूप ले चुकी है, ने अपने कौशल का इस्तेमाल शुरू किया और उनके पिता ने अपने चुनाव के नामांकन में जो जानकारी दी उसमें उनकी,पुत्री व पूजा खेड़कर की संपत्ति का हवाला है। जिनके अनुसार वह क्रीमिलेयर में नहीं आती। उन्होंने गलत जानकारीयों के आधार पर योग्यता से अधिक अक्सर लिये इस पर संच लोक सेवा आयोग ने संज्ञान लेते हुए, उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी है। इसके अलावा आयोग ने भविष्य में किसी भी परीक्षा में उनके शामिल होने पर रोक लगा दी है। और संभव है कि अपनी माता जी के साथ जेल में होगी। पूजा खेड़कर की घटना को मैं एक वैयक्तिक अपराध की घटना के साथ-साथ भारतीय प्रशासनिक सेवा के लोगों में जिस प्रकार की प्रशासनिक, नैतिक गिरावट आ रही है उसके प्रति चिंतित हूँ। भारतीय संविधान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा के

प्रशासनिक सेवा और नैतिकता की कसौटी

अधिकारियों को स्वतंत्र हिस्सा माना है। संविधान के तीन खंभे हैं, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। कार्यपालिका के लिये कई प्रकार के वैधानिक सुरक्षायें संविधान ने दी हैं। हालांकि अकसर इन सुरक्षाओं का दुरुपयोग होता रहा है। सत्ता के चाटुकार बने कार्यपालिका अधिकारी अपराध करते हैं और इस प्रावधान के प्रयोग से वे वैधानिक ढंड से बच जाते हैं। अभी 23 जून 2024 को जब मेरी दो पुस्तकें रसमस्या और समाधान्य तथा श्आमजन और राजनीति्य का विमोचन कार्यक्रम दिल्ली में हुआ। तब उप्र के विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष श्री हृदयनारायण दीक्षित उसमें आये थे और उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सेवाओं के दौर में जो रघुजी ने लिखा है चरित्र और नैतिकता वह तो होना ही चाहिए। उनका कथन गलत नहीं है। क्योंकि प्रशासनिक अधिकारियों का संबंध आम जनता के साथ होता है और बहुतेरी छेटी-छेटी समस्याओं के लिए गरीब और आमजनो को सालों साल दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। ऐसी घटनाओं से लगभग हर वह व्यक्ति जो सत्ता पक्ष या विशिष्टजन की श्रेणी में नहीं है या जिसके पास ऐसी कोई सिफरस्या का माध्यम नहीं है तो उन लोगों की मामूली सी समस्या भी सालों साल यथावत बनी रहती है। मैं अमूमन देखता हूँ कि जब कोई व्यक्ति सांसद या विधायक चुना जाता है, मंत्री या मुख्यमंत्री या अन्य बड़े पदों पर पहुँचता है तो उसे हजारों लोग ऐसे आवेदन करते मिलते हैं जो लगातार दशकों से आवेदन दे रहे हैं न तो उनका हल निकला है और न निकलेगा। परंतु वे अपने कर्तव्य के तौर पर उस उम्मीद में कि शायद कोई सुन ले, मंत्रियों के कार्यक्रमों में जाते हैं। किसी मुर्षी को 2-5 रुपये देकर आवेदन लिखवाते हैं या टाइप कराते हैं और दे आते हैं पर किसी भी मंत्री या अधिकारी ने यह क्यों नहीं सोचा कि आखिर यह लोग इतने वर्ष से आवेदन देने को क्यों लाचार हैं? अगर उनका आवेदन गलत है तो उन्हें कहा जा सकता है और यदि सही है तो उसका हल किया जाना चाहिए। अब विधायकों, सांसदों या मंत्रियों ने जनता दरबार लगाने शुरू किये हैं जिसमें सैकड़ों समस्या से ग्रस्त लोग आते हैं और निवेदन कर चले जाते हैं। उसी क्रम में प्रशासनिक अधिकार भी जन सुनवाई करने लगे हैं। जिलों के कलेक्टर जन सुनवाई की तारीख तय करते हैं। स्वाभाविक है कि जिलेभर के पीड़ितों की भीड़ आ जाती है उनके आवेदन ले लेते हैं, अखबार में छपवाने के लिए मीडिया के लोग बुलाते हैं, एक-दो समस्या को हल करने के आदेश देते हैं और आधा एक घंटे में यह जनसुनवाई समाप्त हो जाती है। उसके बाद उनका क्या

हुआ इसके लिये न कलेक्टरों के पास समय है न सत्ता के पास। सत्ताधीश तो यह चाहते भी नहीं है कि उनके बगैर इशारे के किसी की समस्या का निदान हो। बल्कि उनका पसंदीदा अधिकारी वही होता है जो केवल उनके इशारे पर सही या गलत करता है, इसके अलावा कुछ नहीं करता। आजकल हवाई जहाज या हेलीकाप्टर की सुविधा होने से मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों या केंद्रीय मंत्रियों के दौरे भी आसान हो गये और अकसर यह होता है कि जिस दिन जनसुनवाई होती है उस दिन कोई न कोई वीआईपी या वीवीआईपी या उनसे उच्च अधिकारी जिले में होता है। उन्हें तलब कर लेता है और कलेक्टर की ओर से एसडीएम और एसडीएम की ओर से तहसीलदार आवेदन ले लेते हैं। जैसे डाकिया पोस्ट ऑफिस की डाक लेता है। इतना संवेदनशील प्रशासन और शासन क्या कभी अतीत में रहा होगा, यह भी खोज का विषय है। रजवाड़ों के जमाने में कोई गरीब व्यक्ति आकर शिकायत कर सकता था और राजा त्वरित देता था, न जाँच अधिकारी बैठायें जाते थे न कमेंटियाँ बनती थीं, न रपट मंगाई जाती थी परंतु इस त्वरित न्याय का परिणाम यह होता था कि आमजन सारे समाज में अपराध के दंड के प्रति एक भय व्यक्त हो जाता था। मुगलकाल में भी यह परंपरा चलती थी परंतु भारतीय कार्यपालिका जो अब वास्तव में नौकरशाही में बदल गई है वह आज भी अंग्रेजों की सत्यप्रति जैसी है। हालांकि इसके लिये केवल अधिकारी ही जवाबदार नहीं हैं बल्कि निर्वाचित शासक भी इसके लिए जवाबदार है। कोई मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों से यह नहीं कहता कि तुम्हारा काम राजनैतिक पार्टी चलाना नहीं है आप दलीय भेदभाव से उत्तकर लोकतांत्रिक तरीके से समस्याओं को सुने औ उनका हल करें। ट्रांसफ़ तबादलों की कसौटी भी सत्ताधीशों या ताकतवर लोगों की पसंद या सुशासन अरन्धियां गुस्सा के आधार पर नहीं बल्कि उनकी प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर होना चाहिए। दूसरे अदूरर्शिता और नासमझी ने प्रशासनिक ढांचे को इतना फैला दिया है कि कोई अच्छे से अच्छ व्यक्ति भी कुछ करना चाहे तो उसे अपार बाधाओं को पार करना होता है। इतने दफ्तर, इतने खंड, इतने अधिकारी पैल गये हैं कि बजट का बड़ा हिस्सा तो उनकी सुविधाओं और वेतन पर खर्च हो रहा है परंतु उसके परिणाम कुछ भी नहीं हैं। कर्मचारी संगठन, मजदूर, संगठन, राजनैतिक संगठन यह सब अपने हितों तक सीमित हो गये हैं और उन्हें सत्य-असत्य से कुछ लेना-देना नहीं है, उन्हें केवल स्वहित, दलहित, परिवार हित सर्वोपरि है। हालांकि इसके परिणाम भी राजनैतिक नेतृत्व को ही भोगना पड़ते हैं। पसंदीदा पुलिस अधिकारी वो चाहे

जाति, धर्म या दलीय आधार पर पसंद हो या पैसे के कारण पसंद हो परंतु वह अंततःरू नुकसानदायक ही सिद्ध होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के अपने वनारस चुनाव क्षेत्र के संसदीय चुनाव के परिणाम के निष्कर्षों की उन्होंने क्या व्याख्या की मैं नहीं जानता, परंतु 6 साल से घटकर डेढ़ लाख की जीत और कई मतगणना के चरणों में हार एक प्रकार से उनकी हार ही है। और इसका एक बड़ा कारण उनके पसंदीदा अधिकारी हैं। वे अधिकारी जनता के साथ क्या कर रहे हैं, कितना अन्याय, प्रधानाह्वी कर रहे हैं, इन सवालों पर प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा क्योंकि वे नौकरशाही के बनाये तथाकथित विकास के नाम के मृत् तुष्णा के जाल में फँसे रहे। यहाँ तक हुआ कि बीएचयू की छात्रायें अपनी जायज व मानवीय पीड़ा को लेकर महिला आंदोलन करती रहीं, कुलपति ने उन बेटियों की बात चुनने की जगह उन्हें पुलिस से पिटवाया व लगभग एक वर्ष तक यह अंतसंघर्ष चलता रहा। जब लाचार होकर छात्राओं ने प्रधानमंत्री के दौरे में ही प्रदर्शन की घोषणा की तब कहीं जाकर प्रधानमंत्री ने कुलपति को हटवाया। अगर वह अपने अधिकारियों से पूछते कि यह खबर पूर्व में क्यों नहीं दी, अगर वह मीडिया के प्रचारकों से पूछते और वह सारी खबरें निकलवाते तो जन के साथ भी पाप होता। नौकरशाही भी सबक सीखती और उनकी छवि भी बेहतर होती।

इसी प्रकार बनारस के छोटे दुकानदारों, व्यापारियों को विकास के नाम पर बेदखल करने का मामला भी था, अगर किसी की भी विस्तारित करते हैं तो उसके पहले उसके स्थापना की व्यवस्था होना चाहिये। हजारों लोगों को आपने गुलाम नौकरशाहों ने बगैर वैकल्पिक व्यवस्था, चर्चा के पुलिस के डंडों के दम पर उजाड़ दिया और प्रधानमंत्री उनकी सब ठीक है कि रपट में मस्त रहे यह उदाहरण अकेले प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि अमूमन देश के अधिकांश सत्ताधीशों का है। वे कुर्सी पर पहुँचकर कुछ सुरक्षा के नाम पर या चाटुकारिता में ऐसे घिरे रहते हैं कि उन्हें आम जनता के सुखदुःख या भावना का पता नहीं लगता। अखबार के विज्ञापनों में अब समाज प्रभावित होता। वह केवल व्यक्ति का चेहरा भर जानता है। परंतु देखने में आता है कि देश की सभी सरकारें, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्रियों, मंत्रियों यहाँ तक कि सांसद, विधायक के विज्ञापन राजनीति कर रहे हैं।अब समय आ गया है कि प्रशासनिक अधिकारियों के चयन और प्रशिक्षण में नीति नैतिकता, संवेदनशीलता और जन उत्तरदायित्व को भी कसौटी बनाया जाये। और उन्हें दी गई संवैधानिक सुरक्षा को भी समाप्त किया जाये। सही अर्थों में यही सुशासन या प्रशासन होगा, वर्ना आज जो चल रहा है वह तो सही मायनों में केवल कुशासन ही है।

प्रदीप मिश्र

(लेखक जम्मू-कश्मीर में पत्रकार रह चुके हैं।)

प्रां च अगस्त 2024 को जम्मू-कश्मीर के अनुच्छेद 370 से मुक्त हुए पांच साल पूरे हो जाऐंगे।लद्दाख़ को अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाने से जम्मू-कश्मीर के इतिहास के साथ भूगोल भी बदल गया। इस दौरान आतंकी वारदातें तो हुईं लेकिन लोकसभा चुनाव खासतौर पर नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद इनमें तेजी आ गई है। अहम बात यह कि इनका केंद्र जम्मू क्षेत्र के जिलों में नियंत्रणरेखा के नजदीक पुंछ और राजोरी के अलावा रियासी तक है। एक समय शांत मान लिए गए डोड और किश्तवाड़ में भी गतिविधियां अंजाम दी जा रही हैं। यही नहीं, अंतरराष्ट्रीय सीमा से सटे कठुआ जिले में आतंकी अरसे बाद सक्रिय हुए हैं। इन सबके बीच 2014 के बाद से अब तक नहीं हुए विधानसभा चुनाव के सितंबर-अक्तूबर में होने की अटकलें और सियासी दलों की तैयारियां पूर्ववर्ती राज्य में स्थानीय लोकतंत्र की बहाली की उम्मीद जगा रही हैं। केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद यहां के हालात बेहतर हुए हैं। 2024 में जनवरी से जून तक 1.08 करोड़ पर्यटक यहां पहुंचे। तीन वर्ष में पर्यटकों में बढ़ोतरी का वार्षिक औसत 15.13 प्रतिशत रहा है। यही नहीं, 3 अगस्त तक जम्मू से 4,85,314 श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए खाना हुए। यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन तक चलेगी। 2023 में 62 दिन चली अमरनाथ यात्रा में 4.45 लाख श्रद्धालुओं ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई थी। पर्यटकों और श्रद्धालुओं का यही हैसला पाकिस्तान को बेचैन कर देता है। इस साल जून से अब तक हुई घुसपैठ, सुरक्षा बलों पर हमलों में शहादत से दहशत और असुरक्षा बढ़ गई है। पाकिस्तान के बॉर्डर एक्शन टीम (बैट) ने 27 जुलाई को कुपवाड़ा में नियंत्रण रेखा पार कर हमला कर नापाक इरादे दावा दिए। आठ जनवरी 2013 को बैट के आतंकी पुंछ में हमला कर उत्तर प्रदेश निवासी लांसनायक हेमराज सिंह और मध्य प्रदेश के सैनिक सुधाकर की हत्या के बाद दोनों का सिर काट ले गए थे। कारगिल विजय दिवस के दूसरे दिन हुए इस हमले के पीछे पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों का मंजूबा साफ है। विजय दिवस के 25

साल पूरे होने पर कारगिल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बलिदानियों को श्रद्धांजलि देने के साथ पाकिस्तान को चेतावनी दी थी। कहा था कि सेना आतंकवाद को कुचल देगी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने का दर्द जितना उस समय के प्रधानमंत्री इमरान खान को था, शहवाज ने उससे कम नहीं है। इमरान ने इसे हर मंच पर उठाया लेकिन उन्हें मुंह की खानी पड़ी। पाकिस्तान



को पता है कि जम्मू-कश्मीर के अवाग ने लोकसभा चुनाव में रिकॉर्ड मतदान किया। अब विधानसभा चुनाव में लोगों की भागीदारी भी एफ कॉमिशन बनाकर दुनिया को बता सकती है कि उन्हें अपने वतन और जम्हूरियत से प्यार है और वह इसके पैरोकार हैं। यही नहीं, कारगिल में शिकस्त की कसक भी पाकिस्तान में खसत नहीं हुई है। पराजय पक्का जानने के बावजूद पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल असीम मुनीर नए परवेज मुशरफ़ बनाना चाहते हैं। जम्मू-कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आरके स्वेन भी मानते हैं कि 50-60 प्रशिक्षित आतंकी घुसपैठ कर चुके हैं।

पीओके के भारत में विलय के लिए मुहिम चलाने

वाले डॉ. अमजद अयूब मिर्जा के मुताबिक घुसपैठ करने वालों की संख्या 500 से अधिक है। ये युद्ध के हालात बनाना चाहते हैं, ताकि जम्मू-कश्मीर के विधानसभा चुनाव में खलल पड़े। दरअसल, यह तय है कि चुनाव के बाद पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर को कि जिलेभर के पीड़ितों की भीड़ आ जा सकती है। 2021 से अब तक आतंकी वारदातों में सबसे अधिक 52



शहादत सुरक्षाकर्मियों ने दी है। 20 से अधिक नागरिक भी शिकार हुए हैं। 2021 और 2023 में सुरक्षा बलों पर चार बड़े हमले हुए थे। इनमें बड़ी क्षति हुई थी। 2024 में जुलाई तक ही चार हमले हो चुके हैं। हालात इस कर नाजुक हैं कि 7 से 17 अगस्त तक चलने वाली पुंछ की बूझ अमरनाथ यात्रा के लिए वाहनों के आने-जाने का समय तय किया गया है। 2005 के बाद पहली बार इसकी सुरक्षा अमरनाथ यात्रियों की तर्ज पर की जा रही है। केंद्र सरकार ने मौजूदा हालात के मद्देनजर जम्मू और सांबा में पाकिस्तान की सीमा पर सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) की दो बटालियन ओडिशा से और असम राइफल्स की दो बटालियन मणिपुर से

बुलाकर तैनात की हैं। नितिन अग्रवाल की जगह दलजीत चौधरी को बीएसएफ का नया महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा आतंकी वारदातों को नाकाम करने के लिए स्पेशल ऑपरेशन रूप (एसओजी) संवेदनशील इलाकों में 75 कैप बनाने जा रही है। सुरक्षा बल संयुक्त निगरानी के जरिये पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस रूप (एसएसजी) के घुसपैठ कर चुके कमांडो, स्लीपर सेल, ओवर ग्राउंड वर्कर (ओजीडब्ल्यू), आईएसआई एजेंटों के ताने-बाने को नेस्तनाबूद करेंगे। ऐसा करना जरूरी है, क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है आतंकी हमलों का चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता। याद दिलाया कि 1996 में आतंकवाद के चरम पर होने के बावजूद चुनाव कराए गए थे। वर्तमान हालात को उन्होंने केंद्र सरकार और सुरक्षा बलों की कमजोरी से भी जोड़ दिया।

विधानसभा चुनाव पर पशोपेश के बीच सक्रियता भी है। सितंबर-अक्तूबर में चुनाव हो सकते हैं। पहली बार सरकार बनाने को आतुर भाजपा इसमें सबसे आगे है। जुलाई के पहले सप्ताह में पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जम्मू में तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं। 15 अगस्त तक जम्मू क्षेत्र की सीटों पर मोर्चों के सम्मेलन चलेंगे। विधानसभा चुनाव के प्रभारी केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी दो बार और अर्जुन राम मेघवाल एक बार दौरा कर चुके हैं। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी तरुण चूग उधमपुर-डोड जिले में सात दिन प्रवास कर चुके हैं। दूसरी ओर भाजपा विरोधी दल सात अगस्त को जम्मू में बैठक करेंगे। इसमें नेशनल कांफ्रेंस के साथ पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी और कांग्रेस भी शामिल होंगी। लोकसभा चुनाव में दावेदारी और उम्मीदवारी को लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल तीनों दलों के रिस्ते तल्ल हो गए थे। आश्चर्यजनक तौर पर बैठक में जम्मू-कश्मीर अपनी पार्टी भी शामिल हो सकती है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद पूर्व मंत्री मियां अल्लाफ ने यह पार्टी बनाई थी। गठन के समय से ही इसे केंद्र और भाजपा समर्थक माना जाता रहा है।

जाति न पूछो साधु की

कटाक्ष

सूर्यदीप कुशवाहा

लेखक व्यंग्यकार हैं।

इ जाति है की जाती नहीं। देश - प्रदेश में ही नहीं बल्कि संसद में भी जाति पूछ ली जाती है। सांप चूहा बिछ्छी कुत्ता भालू आदि की जाति होती है।क्योंकि सभी जानवर अलग प्रजाति से है। इंसान की अलग प्रजाति नहीं है।फिर भी इंसान में जाति है। यह अजब है। देश में यह



कहते मिल जाएंगे कि हम जातिवादी नहीं हैं। गजब लोच है।फिर भी नाम में जाति की पूँछ लगा इराते हैं। बड़ी जाति वाले सम्मानित हैं और छोटी जाति वाले उनसे ही अमानित हैं। छोटी जाति वालों को ही इसका रंग है जबकि बड़ी जाति वाले निगरे हैं। पूछता है भारत कि क्या बड़ी जाति वालों की जातिगत उत्थान संस्थाएं हैं? हैं तो फिर बकलोली का दिखावा क्यों? फलाना-ढिमकाना पार्टी जाति

की राजनीति करती हैं। लेकिन आपकी चमकाना पार्टी भी जातिगत मोच से उबर कहा पाई? एसी-एसटी ओबीसी और फारवर्ड कटेगरी है। जाति बंद वर्ग है। अपने अपने जाति से निकलने का रास्ता कहा है? जो छोटा है वह छोटा होगा और जो बड़ा है वह क्यों छोटा होगा। दुर्भाग्य की लपट है।

ये तो हद ही है। बताइए, जाति पूछ रहे हैं। कहावत भी है - जाति न पूछो साधु की। जिस देश में साधु की जाति पूछने तक की मनाही है, वहीं संसद में जाति पूछ रहे हैं। जाति व्यवस्था बंद कर देना चाहिए। सबको भारतीय बना देना चाहिए। जातीयगत जनगणना का विरोध करने वाले तैयार हैं। अब प्लीज कोई यह कहकर बहकाने की कोशिश नहीं करे कि जाति में क्या रखा है। जातीय जनगणना का विरोध करने वाले कोई सकूचा-सकूचा के नहीं, छत्ती ठेक कर बताते हैं। जातीय सभाओं में ही नहीं, घर के अंदर भी बताते हैं। निश्चित ही बताते हैं। लेकिन, क्यों बताते हैं। जाति जनगणना पर इंकार। इसी बात पर संदेह और तकरार है। कोई कैसे उनसे जाति पूछ रहे है? जातिगत जनगणना से जातिगत आकड़े आएंगे तो कौन लाभ से वंचित हो सकता है, किसको डर है। छिपाना कौन चाह रहा है? सबकी पोल खुल जाएगी। उनका झोल दिख जाएगा। राजनीति में गंजब की तुलपाई करते हैं क्योंकि यहीं प्रभु की जाति मिलती है।

गरीबी की कोई जाति नहीं है। महंगाई डायन की भी कोई जाति नहीं है। फिर भी गरीबी पर अत्याचार कर रही हैं।जाति भी अत्याचार का साधन है। जाति की गाली भी गोली-सा काम करता है। बड़े कुल में जन्मे के लिए जाति ही सब कुछ है, बाद में बदलना थोड़ी चाहते हैं।धार्मिकरण किया जा सकता है,लेकिन जाति नहीं बदल सकता। वो जाति की राजनीति करते है। लेकिन दूसरे भी तो वही करते हैं। अपने पकड़ साफ बनते हैं। कान घुम के पकड़ो या सीधा पकड़ो बात तो एक ही है। जाति अंश कुआँ है, जहाँ धकेले जा रहे हैं। चुप रहना ही वाजिब है। इसलिए जाति न पूछो साधु की।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबन्धु परिसर, प्रेस कॉम्प्लेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

संपादक - उमेश त्रिवेदी

(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)

RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923, Ph. No. 0755-2422692, 4059111 Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सम्बन्ध होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

डॉ प्रदीप उपाध्याय

शहर की सभी गटरों अपने प्रिय नाले के बिछोह में दीवानी होकर उबड़-खाबड़ सड़कों पर मिलकर जमा हो गई और विरह गीत गाने लगीं। आखिर बरसों बरस का बिछोह है।हर साल तो उन्हें इसी तरह अपनी सीमा छोड़कर सड़कों पर निकल पड़ना पड़ता है और निराश भाव से वापस लौट आना पड़ता है लेकिन शायद इस बार नहीं।यही सोचकर मेघों के बरसते ही वे सड़कों पर आ गई हैं।

सड़कें भी उनके स्वर में स्वर मिलाकर शोकाकुल होकर अपने भीतर छुपे गुड़ों को अपने आगोश में लेकर शोकाकुल होकर विलाप कर रही थीं। गटरों ने इस बात की परवाह नहीं की कि उन्हें देखकर नदी बन चुकी सड़कों पर लोग गिर -पड़ रहे हैं, स्कूटर, मोटरसाइकिलें बहने लगी हैं।कार-रिक्शा आगे बढ़ने से इंकार कर रहे हैं। माए अपने बच्चों को घरों के भीतर खींच रही है।सिक्केज के खुले चेंबर चलते फिरते आदमी को अपने आगोश में खींच रहे हैं।कुत्ते-बिछी सिर छुपाने की जगह खोज रहे हैं। गाय-भैंस अपनी

नालों से मिलन की आस में उपद्रव करती गटरें

आवारगी भूलकर अपने मालिकों को खोज रही हैं।बच्चे स्कूल से वापस घर पहुंचने के लिए चीख-पुकार मचा रहे हैं और जोर जोर से चिल्ला रहे हैं,उनका रो-रोकर बुरा हाल हुआ जा रहा है,उनपर मास्टर-मास्टरनियां खीज उतार रही हैं। सरकारी कारिंदे घर जाने

की जल्दी में हलकान हुए जा रहे हैं। मृगंडे का ठेला भी गटरों के साथ सड़क पर अपने साजो-सामान के साथ अठखेलियां मचा रहा है।दारू के ठेके पर बैठे दारूबाज अपने चबीने के लिए आहत हैं लेकिन फिर भी अपनी प्रिय गटर के सड़क में विलीन हो जाने पर गमगीन होकर पखे को नीट खिंचें चले जा रहे हैं।

गटरों इन बातों की परवाह नहीं कर रही हैं।वे तो समा जाना चाहती हैं।अपने प्रिय नालों में। लेकिन नाले कहाँ हैं। वे व्याकुल हो उठी हैं। जब-तब उनकी व्याकुलता बढ़ती चली जाती है और वे सड़क पर उतर आती हैं।वे सोचती रहती हैं कि आखिर नाला अन्य नालों के साथ गया तो गया कहां। सरकार भी नालों

को खोजने में असरकारी साबित नहीं हो पाई है।तो आम जन क्या खोज पाएगा। सोचने में आता है कि क्या वह भी अन्य नालों की तरह अपनी प्रिय नदियां में समाने चल पड़ा है। उधर शहर के जलमन होने से हुजूर लोग भी परेशान से नजर आ रहे हैं। पुराने



नक्शे खंगाले जा रहे हैं।उस जमाने के नक्शे जब शहर कस्बा हुआ करता था। कस्बे में कई-कई नाले हुआ करते थे, तालाब हुआ करते थे।गटर और नाले पिछड़े होने और।फिर कभी ब्यूटी पालर का मुंह नहीं देखने के बावजूद वर्षाकाल में अपने कच्चे पक्के स्वरूप में मिलन की बेला में किसी की शिकायत का मौका नहीं देते थे।किन्तु हटा,यह क्या नालों को सीधे जिंदा ही कस्बाह में पहुंचाकर उनपर तनी इमारतों का मुंह शर्म से झुकते हुए किसी ने देखा भी नहीं है। तालाब कालोनी बनकर सिर झुकए बैठे हैं।

हां , गटरों का उपद्रव उन्हें चैन से सोने नहीं दे रहा है तभी तो साहिब बहादुर पुराने नक्शे टटोल रहे हैं, उनको पुराने नक्शे तो मिल रहे होंगे और उनमें दर्ज पुराने नाले भी जिनका विस्तार मुख्य नाले या फिर नदियों तक भी होगा किन्तु कागजों में बहती सच्चाई जमीन पर झूठ बनकर सूखती नजर आ रही है। आखिर कैसे कोई विकसित शहर को वापस पिछड़े कस्बे में परिवर्तित कर सकता है। विकास तो बली चाहता है। नालों की बली चढ़ चुकी है। गटरों अंडरग्राउंड हो जाना चाहती हैं लेकिन क्या करें। शहरीकरण और उसकी मानसिकता की गंगा की को समेटे अब गटरों भी शहर की गंदगी को लेकर सड़क पर बारिश में उपद्रव करने लगती हैं अपने प्रिय नालों को खोजने,उन्से मिलने की आस लिए।

कानून और न्याय

विनय झैलावत

(पूर्व असिस्टेंट सॉलिसिटर जनरल एवं वरिष्ठ अधिवक्ता)



एक बार फिर शाहबानो प्रकरण चर्चा में है। सर्वोच्च न्यायालय के हालिया फैसले ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला के दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के अधिकारों को बरकरार रखा है। यह एक सामाजिक रूप से लाभकारी प्रावधान है। इस फैसले के साथ ही हमने 1985 में शाह बानो मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद एक पूरा चक्कर लगाया है। इसके बाद मुस्लिम महिला के लिए इहत अवधि के दौरान भरण-पोषण का दावा करने के साथ-साथ भविष्य के लिए एक उचित प्रावधान का नया अधिकार बना है।

इस मामले में परित्यक्त पत्नी ने तेलंगाना में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया था। पारिवारिक अदालत ने उसे मासिक भरण-पोषण के रूप में बीस हजार रुपये देने का आदेश दिया। इस बीच, पति ने उसे तलाक दे दिया और दावा किया कि तलाक के बाद वह भरण-पोषण का दावा करने की हकदार नहीं थी। उन्होंने तर्क दिया कि उनके अधिकार अब मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों के संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत है। उनकी ओर से यह तर्क दिया गया था कि चूंकि 1986 का अधिनियम दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 125 के विपरीत तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के लिए अधिक लाभकारी और प्रभावी उपाय प्रदान करता है। इसलिए यह उपाय विशेष रूप से 1986 के अधिनियम के तहत है। इसके अलावा, यह भी कहा गया कि 1986 का अधिनियम, एक विशेष कानून दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों पर हावी है, जो एक सामान्य कानून है। लेकिन इन दोनों दलों की को तेलंगाना उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। हालांकि, रखरखाव की राशि को घटाकर दस हजार रुपये प्रतिमाह कर दिया। इस आदेश के खिलाफ पति ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने एक विस्तृत फैसले में, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के पत्नी के अधिकार को बरकरार रखा। यह इस आधार पर था कि यह एक सामाजिक रूप से लाभकारी प्रावधान है और उक्त अधिकार 1986 के अधिनियम से समाप्त नहीं होता है। इससे प्रचलित विवाद को विराम मिल गया है।

इस मुद्दे पर एक महत्वपूर्ण निर्णय डेनियल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ (2001) है। इसने नए

तलाक के बाद भी भरण-पोषण का अधिकार

उच्चतम न्यायालय के निर्णय ने अब अस्पष्टता को दूर कर दिया है और स्पष्ट रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि नए अधिनियम ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के लाभकारी प्रावधान के तहत तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों को समाप्त नहीं किया है। यह निर्णय दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मुस्लिम विवाहित महिलाओं सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। साथ ही यह धारा सभी गैर-मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। जहां तक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 विशेष विवाह अधिनियम के तहत उपलब्ध उपायों के अलावा विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित और तलाकशुदा ऐसी सभी मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है।

अधिनियम की संवैधानिक वैधता की जांच की (लतीफी सर्वोच्च न्यायालय में शाह बानो के वकील थे)। सर्वोच्च न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने यह अभिनिर्धारित करते हुए कि अधिनियम संवैधानिक रूप से मान्य है। तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए धारा 3 (ए) की एक नवीन व्याख्या प्रदान की। इसने अभिनिर्धारित किया कि पूर्व पति को इहत अवधि के तीन महीनों के लिए भरण-पोषण का भुगतान करना आवश्यक है। इसके अलावा, इहत अवधि के भीतर उसके पूरे जीवन के लिए एक उचित और उचित प्रावधान भी प्रदान करना भी आवश्यक है।

सर्वोच्च न्यायालय ने इसे इस अर्थ में समझाया कि पति को तलाकशुदा पत्नी की भविष्य की जरूरतों पर विचार करने और इन जरूरतों को पूरा करने के लिए पहले से ही प्रारंभिक प्रावधान करने की आवश्यकता थी। जब वह सवाल आया कि क्या दानियाल लतीफी के फैसले ने तलाकशुदा मुस्लिम महिला पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के लागू होने के मुद्दे को स्पष्ट किया था, तो यह माना गया कि यह विवाद का मुख्य मुद्दा नहीं था। हालांकि, यह कहा गया था कि धारा 125 के तहत अधिकारों का कोई स्पष्ट उन्मूलन नहीं था। सन 1986 के अधिनियम को लागू करते समय न तो विधायिका द्वारा इसका इरादा था और न ही इसकी कल्पना की गई थी। यह देखा गया कि दोनों प्रावधानों द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पूरी तरह से अलग हैं। क्योंकि धर्मीनरपेक्ष प्रावधान उक्त अधिकारों को लागू करने के लिए खुद को बनाए रखने में असमर्थता को निर्धारित करता है। जबकि 1986 अधिनियम की धारा 3 किसी की क्षमता या खुद को बनाए रखने में असमर्थता से स्वतंत्र है। इस प्रकार, दो कथित परस्पर विरोधी विधायी संरक्षणों के बीच एक सामंजस्यपूर्ण और उद्देश्यपूर्ण दृष्टिकोण अपनाकर, तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकारों की रक्षा की गई।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला भरण-पोषण के सभी अधिकारों की हकदार है। जैसा कि देश में अन्य समान रूप से स्थित महिलाओं के लिए उपलब्ध है और अन्याय एक व्याख्या संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 के माध्यम से प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करेगी। इन प्रावधानों

के आधार पर मजिस्ट्रेट के पास निहित शक्ति और अधिकार क्षेत्र की प्रकृति दंडात्मक नहीं है और न ही यह उपचारात्मक है।

यह एक निवारक उपाय है। यह भी कहा गया कि हालांकि ऐसा कोई भी अधिकार संबंधित पक्षों पर लागू किसी भी व्यक्तिगत कानून के परिणामस्वरूप मौजूद हो सकता है या



नहीं भी हो सकता है, लेकिन वे धर्मीनरपेक्ष प्रावधान के खिलाफ विशिष्ट रूप से और स्वतंत्र रूप से मौजूद रहेंगे। दानियाल लतीफी और अन्य बनाम भारत संघ में 2001 के ऐतिहासिक फैसले में शीर्ष अदालत ने कहा कि यदि पति इहत अवधि के भीतर भरण-पोषण के लिए उचित और निष्पक्ष प्रावधान करने में विफल रहता है, तो पत्नी दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है। यह दुर्लभ नहीं है, लेकिन वही निर्णय शाह बानो मामले में लिया गया था। जहां न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाया था कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 सभी नागरिकों पर लागू होती है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, बिना भेदभाव के और इसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी अधिसूचित किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 (3) मुसलमानों पर भी लागू होती है। धारा 125 और मुस्लिम पर्सनल लॉ

के बीच किसी भी संघर्ष के मामले में, धारा 125 प्रचलित है। लेकिन फिर भी जवाब अस्पष्ट था। क्योंकि इसे मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, 1986 द्वारा रद्द कर दिया गया था और 2001 में कानून की वैधता को बरकरार रखा गया था। लेकिन मोहम्मद अब्दुल समद मामले में फिर से यह निर्णय लिया गया है कि एक महिला अपने पूर्व पति के खिलाफ दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा कर सकती है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति जे. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने तेलंगाना उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ इस मुस्लिम पति की अपील को खारिज कर दिया। इसमें उसकी पूर्व पत्नी को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण की मांग करने की अनुमति दी गई थी।

इस दृष्टिकोण से न्यायमूर्ति नागरत्ना ने राय दी कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 एक सामाजिक न्याय उपाय के रूप में "संविधान के पाठ, संरचना और दर्शन में अंतर्निहित है"। रखरखाव का उपाय बेसहारा, परित्यक्त और महिलाओं के वंचित वर्गों के लिए सफलता का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह सामाजिक न्याय के संवैधानिक दर्शन का एक क्षण है जो एक तलाकशुदा महिला सहित भारतीय पत्नी को लिंग आधारित भेदभाव, नुकसान और अभाव की बेड़ियों से मुक्त करने का प्रयास करता है।

न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने अपने फैसले में यह भी उल्लेख किया कि तीन तलाक के अवैध तरीके से तलाक लेने वाली मुस्लिम महिलाएं (जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित किया है और मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 द्वारा अनाथ घोषित किया गया है, वे भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा

125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने की हकदार हैं। अदालत ने आगे कहा कि यह भरण-पोषण अधिकार मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम 2019 के तहत प्रदान किए गए उपाय के अलावा है, जो निर्दिष्ट करता है कि एक महिला, जिसे तीन तलाक दिया गया है, वह अपने पति से निर्वाह भत्ता का दावा करने की हकदार होगी।

इनके अलावा इस मामले में यह निर्णय दिया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 मुस्लिम विवाहित महिलाओं सहित सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होती है। साथ ही यह धारा सभी गैर-मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं पर भी लागू होती है। जहां तक तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं का संबंध है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 विशेष विवाह अधिनियम के तहत उपलब्ध उपायों के अलावा विशेष विवाह अधिनियम के तहत विवाहित और तलाकशुदा ऐसी सभी मुस्लिम महिलाओं पर लागू होती है। यदि मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम कानून के तहत विवाहित और तलाकशुदा हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के साथ-साथ 1986 के अधिनियम के प्रावधान लागू होते हैं। मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के पास दोनों कानूनों में से किसी एक या दोनों कानूनों के तहत उपचार लेने का विकल्प है।

यह पहली बार नहीं है जब सर्वोच्च न्यायालय अर्शिया रिजवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य जैसे मुद्दों पर फैसला दे रही है। मामला, 2022, रजिया बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश मामला, 2022, और शकीला खातून बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, मामला, 2023, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इहत अवधि पूरी होने के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा करने के लिए एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के अधिकार की पुष्टि की है। इसके अलावा मुजीब रहमान बनाम तस्लीमा मामला, 2022 में, केरल उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने कहा कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के तहत तब तक भरण-पोषण की मांग कर सकती है जब तक कि उसे 1986 अधिनियम की धारा 3 के तहत राहत नहीं मिल जाती। इसलिए, इस फैसले को अंतिम कदम नहीं माना जा सकता है। यह भविष्य में कई मोड़ भी ले सकता है।

सामयिक

यशवंत गोरे

लेखक व्यंग्यकार हैं।



वारिशा का मौसम शुरू होते ही अखबारों,सोशल मीडिया में वृक्षारोपण कार्यक्रमों के समाचारों की बाढ़ सी आ जाती है। अखबारों के पन्नों पर वृक्षारोपण करते हुए नेताओं के फोटो से भरे दीखते हैं। यह सिलसिला हम हर साल और वर्षों से देखते आ रहे है। कॉलोनिनों. हाउसिंग सोसायटियों , शिक्षा संस्थानों, सरकारी एवं निजी स्तर पर हर वर्ष वृक्षारोपण कर करोड़ों पौधों को लगाया जाता है। हर वर्ष एक जुलाई से सात जुलाई तक देश में वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए हरियाली महोत्सव भी मनाया जाता है। मध्यप्रदेश के इंदौर में प्रदेश सरकार की और से एक ही दिन में ग्याहद लाख पौधे लगाकर ‘ गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकार्ड ’ में अपना नाम दर्ज किया है। इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित थे। मध्यप्रदेश सरकार ने इस वर्ष पांच करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भी ‘ एक पेड़ मां के नाम’ अभियान चलाकर देश वासियों से अपील की है कि इस अभियान से जुड़ कर अपने माता जी के साथ या माताजी की स्मृति में एक पेड़ अवश्य लगाएं। ऐसे अभियानों में देश वासी भावनाओं के साथ जुड़ तो जाते है परन्तु , एक बार पौधा रोपने के बाद लगाए गए पौधों में से कितनों का संरक्षण होता है और उसमें से कितने वृक्ष बनकर बड़े हो रहे है सुध लेने वाले लोग कम ही मिलेंगे। मध्य प्रदेश में

उपयोगिता के अनुसार ही वृक्षारोपण किया जाना जरूरी

इस प्रकार के अभियान पहले भी चलाये गए है। पेड़ लगाने का लक्ष्य तो निर्धारित किया जाता है , परन्तु सड़कों के निर्माण ,मेट्रो की सुविधा और विकास के नाम पर कितने पेड़ों की बली दी जा रही है इसकी गिनती कोई नहीं करता।

हर वर्ष काटे गए वृक्षों एवं लगाए गए पौधों का क्या अनुपात होता है यह भी एक अध्ययन का विषय है। दिन प्रतिदिन होते जलवायु परिवर्तन और तापमान में अंतर, ऋतुओं के कालचक्र बदलने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि नए वृक्ष तैयार होने की अपेक्षा पुराने वृक्षों की कटाई निश्चित ही अधिक हो रही है।

पौधारोपण करते समय यह ध्यान रखा जाय कि जहाँ पौधा रोपा जा रहा है वह स्थान उस पौधे के फलने -फूलने के लिए उपयुक्त वातावरण आदि की दृष्टि से अनुकूल है कि नहीं। कालोनियों, हाउसिंग सोसायटी में उत्साही पर्यावरण प्रेमी बड़-चढ़ कर उत्साह में पौधरोपण कर तो देते है , परंतु उस समय यह ध्यान नहीं रखा जाता कि रोपा गया पौधा बड़ा होकर परिसर या आवासों को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा?

वृक्षारोपण करते समय स्थान का चयन हम ऐसा करें जहां उसकी उपयोगिता अधिक उपयुक्त हो. वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण को कम करने वाले वृक्षों को शहरी क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे लगाए तो ज्यादा उपयोगी होंगे. नीम, पीपल, बरगद, जामुन, कटहल अर्जुन, अशोक जैसे पेड़ जो प्रदूषण को काम करते है. कृषि भूमि पर अन्य फसलों के साथ फलदार एवं औषधीय

वृक्षों जैसे आम, अमरुद, आंवला, इमली, कटहल, बौंस, सागवान को लगाएं तो इससे कृषक को दोहरा लाभ होगा. एक तो मिट्टी कटाव को रोक कर भूमि सुधार में उसे मदद मिलेगी क्योंकि उनकी जड़ें जमीन



में गहरे में जाने से बारिश के पानी को गहराई तक पहुँचाने में मदद करती है तथा जलस्तर को बढ़ाने के साथ मिट्टी के कटाव को भी रोकती है। दूसरा लाभ फलों एवं लकड़ी से किसान को अतिरिक्त आर्थिक

लाभ भी होगा। मंदिर परिसरों या उसके आसपास ऐसे पौधे लगाए जाए जो धार्मिक महत्व से पवित्र माने जाते है. ऐसी जगहों पर बेल,पीपल, बरगद, गुलर, पलाश, मंदार, कदंब जैसे वृक्षों को लगाया जाना ज्यादा उपयोगी

होगा. पहाड़ी इलाकों में बांज, अखरोट, नाशपाती, अंजीर, खुबानी जैसे पौधों का रोपण उनके अनुकूल होता है। .

प्रसिद्ध पर्यावरणविद एवं चिपको आंदोलन के प्रेरणा स्रोत

पद्मभूषण श्री सुन्दरलाल बहुगुणा ने हमेशा इस बात पर बल दिया कि विदेशी प्रजाति के पौधे जैसे यूकेलिटपस, ल्यूसिन, प्रसोपीय जैसे वृक्षों के बजाय देशी वृक्षों को लगाना चाहिए।

हमारे यहाँ कुछ फलदार वृक्ष दुर्लभ होते जा रहे है उन्हें बचाए रखना भी जरूरी है जामुन, खिरनी, करोंदे, विलायती इमली , इमली , शहतूत , खजूर जिनकी किसी समय बहुतायत थी तथा उनसे प्राप्त फलों को कभी खरीद कर नहीं खाया जाता था, परंतु अब खरीद कर भी खाने को नहीं मिलते। शहरी क्षेत्र की नई पीढ़ी तो इनमें से कई फलों से अनभिज्ञ सी है। कोरोना वायरस में इम्युनिटी बढ़ाने के उपायों में भारतीय बाजोन में उपयोग आने वाले मसालों की उपयोगिता साबित हुई है. देशी -विदेशी बाजारों में भारतीय मसालों की मांग अचानक बढ़ गई है ऐसे में काली मिर्च, इलायची, अरक, हल्दी, जीरा, तेजपान दालचीनी आदि मसाले पैदा करने वाले को पौधों को बहुतायत से लगाए जाए तो आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा की दिशा को भी बल मिलेगा. इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रिकल्चर रिसर्च (आई. सी. ए. आर) के महानिदेशक डॉ. टी. महापात्रा का कहना है कि भारतीय मसालों की गुणवत्ता अच्छी है, जबकि हमारे यहाँ इनके उत्पादन में विशेष ध्यान नहीं दिया जाता जिनका उत्पादन खराब पड़ै भूमि और अंसिचित भूमि पर भी किया जा सकता है। इन फसलों को अच्छे से और व्यापारिक दृष्टिकोण से उत्पादन करने की आवश्यकता है।

सावन माह विशेष

अमित राव पवार



हिंदू धर्म में हर माह का अपना एक महत्व व अर्थ है। हर एक हिन्दू माह में महत्वपूर्ण दिन,पर्व,व्रत,उत्सव, त्योहारों का रहस्य छुपा हुआ है। हिन्दू नववर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होकर फाल्गुन पर समाप्त होता है। यानी नवरात्रि से लेकर महाशिवरात्रि तक। जहां हिंदू वर्ष आद्यशक्ति से प्रारंभ हो रहा है,वही आदिदेव पर वर्ष का समापन होता नजर आता है। यह क्रम चक्र युगों-युगों से चला आ रहा। यहीं हिंदू और सनातन धर्म है। यह सम्पूर्ण संसार स्त्री और पुरुष दोनों से संचालित होता है। यह बात हिन्दू वर्ष प्रारंभ से लेकर समापन तक हमें दिखाई देती है।प्रकृति सदियों से मनुष्य को ऋतु परिवर्तन के साथ उसमें छिपी हर एक बात का संकेत देती है कि मनुष्य प्रकृति के साथ तालमेल करते हुए कैसे स्वस्थ और मस्त रह सकते है।

हमें शिवशक्ति यह संदेश भी दे रहे है। कि सांसारिक परिवार (दोपत्य जीवन) जीवन स्त्री-पुरुष के बिना चलना संभव न के बराबर है। किसी एक के न होने से गृहस्थी डगमगा जाती है। आज के दौर में जहां यूरोपीय सभ्यता,पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में 'लव इन रिलेशनशिप' का चलन हमारे भारतीय संस्कृति,देश में भी शनैः शनैः शुरू हो रहा है। यह सनातन धर्म या हिंदू धर्म का आधार नहीं है।और न ही हमारा सनातन इसे स्वीकारता है। कालगणना के आधार पर भगवान शिव को सबसे अधिक पसंद आने वाला हिंदू धर्म कापांचवा माह सावन का है।इसी माह से आगे आने वाले महीनों में शिव परिवार का आगमन होता है।सावन का संपूर्ण माह शिव के पूजन का,इसके बाद शिव परिवार से श्रीगणेश का

शिव का प्रकृति से पूजन कावड़ यात्रा

आगमन,तत्पश्चात नवरात्रि,माता का आगमन और पुत्र कार्तिक के माह की पूर्णिमा से चातुर्मास का समापन

ताकत से जुड़ना है। इन सब बातों का पारिवारिक जीवन में मनुष्य के समावेश होना अति आवश्यक

है वह शिव के रुद्र रूप को दर्शाता है। इन तीनों का पूजन कर कांवड़ यात्रा शिव मन्दिर के लिए आरंभ करते है।



तथा फिर योगनिद्रा ‘ध्यान’ से जागकर श्रीहरि सुष्टि संचालन का कार्यभार संभलते है। शिव के निमित्त सावन माह में निकाली जाने वाली कांवड़ यात्रा मनुष्य जीवन को बहुत कुछ सीख देती है।

कांवड़ यात्रा जीवन यात्रा का संदेश है। इसका तात्पर्य उद्देश्य,अनुशासन,ईमानदारी, समर्पण, सात्विकता, आत्मविश्वास, धैर्य-सयम तथा वैराग्य के साथ ईश्वर

है।तभी वह अपने सांसारिक जीवन में सफल हो सकता है।कावड़िया,कांवड़ उठाने वाला शिवयोगी के तरह रहता है। जो किसी भी प्राणी का मन,वाणी,कर्म से अहित नहीं करते। ब्रह्मा,विष्णु, महेश तीनों का समावेश इस कांवड़ में होता है। धर्मशास्त्र के आधार पर कांवड़ में दो जल पात्र जिन्हें ब्रह्मघट व विष्णुघट तथा बांस की डंडी को सुंदर रूप में सजाकर जो प्रतीक

कावड़ यात्रा शिवों भूत्वा शिवम जयते अर्थात शिव की पूजा शिव बनकर करो को चरितार्थ करती है। कावड़ यात्रा क्यों, किसलिए और किसके माध्यम से युगों पूर्व प्रारंभ की गई। इन सब बातों का उल्लेख हमारे धर्मग्रंथो में विस्तृत वर्णन के साथ मिलता है।

किंतु एक बात यह समझ आती है,कि कावड़ यात्रा प्रकृति से जुड़ने का मनुष्य के लिए सरल व आसान माध्यम

हिंदू धर्म में हमें दिखाई देता है।वर्षा ऋतु के समय चारों ओर हरियाली आँखों की रोशनी को जहां प्रसन्नता से भर देती,वही नंगे पांव चलने से शरीर के रक्त प्रवाह संचार को गति मिलती। जिससे अनेक रोगों का नाश होता है। साथ ही साथ यह कावड़ यात्रा शिव के गणों की तरह ही सामाजिक सद्भावना का परिचय देती। इस यात्रा में हर एक वर्ग के लोग ऊँच-नीच,अमीर-गरीब,मालिक-नौकर,साधु-संत,गृहस्थ हर उम्र के लोग,वैचारिक-व्यवहारिक मतभेद-मनभेद, भुलाकर-मिटाकर सब अपने शिव की इस कावड़ यात्रा में मंत्रमुग्ध होकर बम-बम भोले,हर हर महादेव जयकारे के साथ प्रकृति के आनंद में सम्मिलित हो जाते है। यही विशेष बात इस भारतीय परंपरा-संस्कृति और धर्म में दिखाई देती है। शिव का प्रकृति से पूजन,कावड़ यात्रा हमको जान देती है कि शिव के गुणों को आत्मसात करें। काम,क्रोध,मोह,मद,लोभ को त्याग कर मनुष्य को अपना जीवन सत्यम,शिवम, सुंदरम बनाना चाहिए। भगवान शिव की चरण में बैठकर उनके स्वरूप को जाने। श्री शिवपुराण में भगवान शिवमहिमा का वर्णन निहित है। शिव प्रकृति संतुलन के देवता भी है। इसलिए उनकी स्तुति तथा वंदना करना सम्पूर्ण सावन माह श्रेष्ठ माना गया है। इसमें भी सावन माह की शिवरात्रि का दिन उत्तम माना जाता है।शिव की लीला व उनको समझना आसान नहीं है।शिव के पूजन के लिए इस समय प्रकृति भी अपने नए स्वरूप में दिखाई देती है।धरती पर कुछ नहीं था तब भी वे थे।आदिदेव व आदियोगी भी वे है,इनके मंत्रोच्चारण में कहा जाता,आकाशे तारकेलिंगम् , पाताले हाटकेश्वरम् मृत्युलोकं च महाकालम्,त्रयलिंगम् नमोस्तुते।। अर्थात आकाश में तारक लिंग,पाताल में हाटकेश्वर लिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर। तीनों लोकों में व्याप वे सर्वोच्च ईश्वर शिव है।

केंद्रीय मंत्री डीडी उईके ने अपने लोकसभा क्षेत्र में विभिन्न ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए रेल मंत्री को लिखा पत्र

● बैतूल जिले को मिलेगा कई सुपर फास्ट ट्रेनों का स्टॉपेज,

बैतूल। यदि सब कुछ ठीक ठाक रहा तो आने वाले समय में बैतूल संसदीय क्षेत्र के कई स्टेशनों पर प्रमुख ट्रेनों के स्टॉपेज का लाभ मिलेगा। क्योंकि स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर ट्रेनों के स्टॉपेज को महत्व देते हुए स्थानीय सांसद और केंद्रीय राज्यमंत्री दुर्गादास उईके ने अपने लोकसभा क्षेत्र में करीब एक दर्जन ट्रेनों के विभिन्न स्टेशनों पर स्टॉपेज की मांग की है। यदि इनमें से आधी भी ट्रेनों का स्टॉपेज भी संसदीय क्षेत्र को मिलता है तो आवागमन की सुविधाओं में जबरदस्त इजाफा होगा। इसके लिए केंद्रीय मंत्री ने रेल मंत्री को पत्र लिख कर तेलंगाना, एपी, अयोध्या, रामेश्वर और हिमसागर एक्सप्रेस के स्टॉपेज की मांग की है। मंत्री बनने के बाद श्री उईके ने पिछले दिनों संसदीय क्षेत्र टिमरनी में दो प्रमुख ट्रेनों का स्टॉपेज करवाया। उईके ने दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके बाद केंद्रीय राज्य मंत्री उईके ने संसदीय क्षेत्र के विभिन्न स्टेशनों में करीब 25 ट्रेनों के स्टॉपेज करने के लिए रेल मंत्री अधिनी वैष्णव को पत्र लिखकर ट्रेनों के स्टॉपेज करने का अनुरोध किया है। पत्र में उन्होंने बताया है कि बैतूल अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित क्षेत्र है। क्षेत्र की जनता एवं व्यापारियों को चिकित्सा, रोजगार और अन्य कार्यों के लिए प्रतिदिन नागपुर, जबलपुर, भोपाल जैसे शहरों में आना-जाना लगा रहता है। कई ट्रेनों का समय पर स्टॉपेज न होने से असुविधा को देखते हुए संसदीय क्षेत्र के प्रमुख स्टेशनों पर करीब 25 ट्रेनों के स्टॉपेज का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि बैतूल में महानदी एक्सप्रेस को दोबारा शुरू करने की मांग उठी थी, लेकिन उसी समय पर सप्ताह में छह दिन स्वर्ण जयंती एक्सप्रेस बैतूल आ जाती है। इसी वजह महानदी एक्सप्रेस को शुरू करने की उतनी जल्दत नहीं है। इसकी अपेक्षा हैदराबाद शहर को जोड़ने के लिए तेलंगाना और एपी एक्सप्रेस की ज्यादा जरूरत है। यदि महानदी को शुरू करने की बजाए यह दोनों ट्रेने बैतूल में रुकती है तो लोगों को खासी सुविधाएं मिलेंगी।

इन स्टेशनों पर स्टॉपेज की रखी मांग

रेल मंत्री को लिखे पत्र में श्री उईके ने बैतूल में अयोध्या-रामेश्वर एक्सप्रेस, हिम सागर एक्सप्रेस, एपी एक्सप्रेस, तेलंगाना एक्सप्रेस के स्टॉपेज का अनुरोध किया है। वहीं आमला रेलवे स्टेशन पर समता, संघमित्रा एक्सप्रेस, मुल्ताई स्टेशन पर अमरावती-जबलपुर, इंदौर- नागपुर एक्सप्रेस, बरबटपुर में अंडमान, पैंचवली, छेहरामहु में पैचवैली, छैनरा में कुशीनगर, दानापुर-पुरगे, हैदराबाद-अजमेर एक्सप्रेस, हवाई में सचखंड, मौला एक्सप्रेस और टिमरनी में पंजाब मेल, कामायनी, सचखंड, गोवा एक्सप्रेस के स्टॉपेज करने और आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है। पत्र की प्रतिलिपि रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष, मध्य रेलवे मुम्बई के महाप्रबंधक और डीआरएम नागपुर-भोपाल को भी प्रेषित की गई है। श्री उईके ने बताया कि घोड़ाडोंगरी स्टेशन पर ट्रेनों के स्टॉपेज के लिए किसी ने मांग पत्र नहीं सौंपा। यहां पहले से ही पर्याप्त ट्रेनें रुक रही है। उसके बावजूद यदि घोड़ाडोंगरी क्षेत्र से कोई मांग पत्र आता है तो प्राथमिकता से पत्र लिखकर ट्रेनों के स्टॉपेज की मांग की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले के हर क्षेत्र में सुविधाएं दिलाता उनकी पहली प्राथमिकता है। किसी भी क्षेत्र की उम्मेदा नहीं की जाएगी।

रामटेक पहाड़ी पर एसपी व गायत्री परिवार ने किया पौधारोपण



बैतूल। आमला बैतूल मार्ग के हसलपुर के समीप स्थित रामटेक पहाड़ी पर अखिल विश्व गायत्री परिवार के द्वारा वृक्षगंगा अभियान के तहत व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण का आयोजन किया है। भारी बारिश होने के बाद भी समिति के द्वारा वृक्षारोपण किया गया है। यहां पर 3 सैकड़ से अधिक करंजी के पौधे लगाए गए हैं। पौधरोपण के कार्यक्रम में बैतूल एसपी निश्चल झारिया, नायब तहसीलदार श्याम बिहारे समेले, टीआई सत्यप्रकाश सक्सेना, नितिन पटेल चौकी प्रभारी तथा नगरपालिका अध्यक्ष नितिन गाडे व गायत्री परिवार, अधिवक्ता, जनप्रतिनिधि मौजूद थे। साथ ही बोखड़ी चौकी में एसपी श्री निश्चल एन झारिया के द्वारा वृक्षारोपण किया है।इस अवसर एसपी झारिया ने कहा कि वृक्षारोपण हमारे भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सभी को एक पौधा लगाना चाहिए, एवं उसकी देखभाल भी करना चाहिए।

बैतूल 98 हजार ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर आए बैतूल

रोबोटिक सर्जरी में हासिल है महारत, बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड

बैतूल। देश में रोबोटिक सर्जरी के पायनियर माने जाने वाले एवं मैक्स हेल्थ केयर न्यू दिल्ली के चेयरमैन डॉ. प्रदीप चौबे ने रोबोटिक सर्जरी में ही सबसे तेज 100 रोबोटिक सर्जरी करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा एक साल में 623 ऐसी सर्जरी करने का रिकार्ड भी उनके नाम है। इसके साथ ही डॉ. चौबे ने अब तक लगभग 98 हजार ऑपरेशन किए हैं और देश में लगभग चिकित्सकों को सर्जरी के संबंध में प्रशिक्षित भी किया है। ऐसे दिग्गज डॉ. प्रदीप चौबे कल कुछ घंटों के लिए पारिवारिक कारणों से बैतूल आए थे।

पीयूष तिवारी के मामा है डॉ. चौबे-- जिला उद्योग संघ के सचिव एवं सक्रिय समाजसेवी पीयूष तिवारी के पिता वेटनी सर्जन डॉ. जीएस तिवारी का गत दिनों निधन हो गया था। परिवार में शोक संवेदनाएं व्यक्त करने पीयूष तिवारी के मामा एवं देश के विख्यात सर्जन डॉ. प्रदीप चौबे कल कुछ समय के लिए बैतूल आए एवं श्री तिवारी के कोसमी स्थित निवास पर शोक संवेदनाएं व्यक्त करने के बाद वापस दिल्ली लौट गए हैं।

डॉ. चौबे का बैतूल से है पुराना नाता-- डॉ. चौबे के पिता डॉ. रामदुलारे चौबे सन 1919 के दौरान बैतूल में कोठीबाजार स्थित रामकृष्ण मंदिर के सामने निवास करते थे। उस समय देश में गिने-चुने डॉक्टरसं हुआ करते थे। इस तरह से डॉ. चौबे का बैतूल से बहुत पुराना नाता रहा।



पदमश्री से सम्मानित हो चुके हैं डॉ. चौबे-- पूर्व राष्ट्रपति केआर नारायण ने डॉ. प्रदीप चौबे को उनकी सेवाओं के लिए देश के बड़े सम्मान पदमश्री से सम्मानित किया था। बौद्ध धर्मगुरु एवं विश्व प्रख्यात दलाई लामा का नई दिल्ली में आपरेशन करने वाले डॉ. चौबे ने कई बड़े नेताओं के भी स्वास्थ्य परीक्षण एवं सर्जरी का कार्य किया है। इसके अलावा पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम भी अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए डॉ. चौबे की ही सेवाएं लेते थे। वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डॉ. चौबे की सेवा भावना एवं योग्यता के कायल है।



इन संस्थाओं का किया प्रतिनिधित्व-- लंदन से एफआरसीएस डिग्री प्राप्त डॉ. प्रदीप चौबे ने जबलपुर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस और एमएस किया था। डॉ. चौबे एशिया पैसिफिक हर्निया सोसायटी के फाउंडर अध्यक्ष, इंटरनेशनल फेडरेशन फार द सर्जरी ऑफ ओबेसिटी एवं मेटाबोलिक डिसऑर्डर के निर्वाचित अध्यक्ष, आईएफएसओ एशिया पैसेफिक के अध्यक्ष के अलावा भी अनेको सरकारी समितियों और सामाजिक संस्थाओं का मेंबर रहे हैं। और वर्तमान में भी कई संस्थाओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

स्कूल पहुंचते ही शिक्षिका बन गई विधायक गंगा उईके, बच्चों को पढ़ाया, किए सवाल

बैतूल/भौरा। जिले के घोड़ाडोंगरी विधानसभा क्षेत्र की विधायक गंगा सज्जन सिंह उईके द्वारा शनिवार को स्कूल एवं छात्रावास का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान एक बार फिर उनका पुराना रूप देखने को मिला। वे स्कूल पहुंची तो बिल्कुल पहले की तरह शिक्षिका के अंदाज में उन्होंने बच्चों को पढ़ाया भी और सवाल-जवाब भी किए। गौरतलब है कि विधायक गंगा उईके विधायक बनने के पहले शिक्षिका ही थी। ऐसे में आज एक बार फिर उनका शिक्षिका वाला रूप देखने को मिला। स्कूल में वे पहुंची तो उन्होंने व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश तो दिए ही, पहले की तरह शिक्षकीय दायित्व का निर्वहन भी उन्होंने किया। इसके साथ ही बच्चों की पढ़ाई-लिखाई का स्तर भी उन्होंने परखा।

धपाड़ा में दिए यह निर्देश-- उन्होंने बालक छात्रावास धपाड़ा का निरीक्षण किया। इस दौरान स्टाफ



को साफ-सफाई नियमित करवाने, बाथरूम के टूटे गेट लगवाने, बच्चों को ताजा भोजन देने और कपड़े टांगने हेतु हेंगर आदि मूलभूत सुविधाएं देने के निर्देश दिए। इस दौरान शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय



धपाड़ा में खुले बिजली के तार उन्होंने देखे। इस पर वहां बोर्ड लगाने एवं बरामदे में पड़ी कबाड़ सामग्री को स्टोर में रखने, विद्यालय परिसर की साफ-सफाई के निर्देश दिए गए। विधायक गंगा उईके द्वारा कक्षाओं में

जाकर निरुशुकक पाठ्य पुस्तक की प्राप्ति की जानकारी ली गई। साथ ही विद्यार्थियों से पढ़ाई की जानकारी भी ली गई।

स्कूल में टपक रहा था पानी-- शासकीय माध्यमिक शाला धांसई में कमरों में पानी टपक रहा था। इसके लिए तत्काल सुधार के निर्देश दिए गए। मध्यान्ह भोजन योजना की जानकारी ली गई। समूह को गुणवत्ता पूर्ण शुद्ध भोजन देने के निर्देश दिए गए। हार्ड स्कूल सातलदेही में तत्काल अतिथि शिक्षक की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए। शासकीय माध्यमिक शाला बंजारीढाल एवं छात्रावास बंजारीढाल का निरीक्षण कर व्यवस्था सुधार के निर्देश दिए गए। विधायक द्वारा निरीक्षण में सड़कों की बदहाली, पुल, पुलिया व रपटों की खराब स्थिति पर नाराजगी व्यक्त की गई। निरीक्षण में अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शासपुर, तहसीलदार शाहपुर, बीइओ शाहपुर एवं घोड़ाडोंगरी साथ रहे।

आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिन पर पतंजलि ने मनाया जड़ी बूटी दिवस

जिला कार्यालयमें हुआ औषधीय यज्ञ, सैकड़ों जड़ी-बूटियों का वितरण एवं रोपण



बैतूल। पतंजलि योग समिति और भारत स्वाभिमान न्यास ने आचार्य बालकृष्ण महाराज का जन्मदिवस बड़ी धूमधाम से जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया। इस अवसर पर जिले भर में पतंजलि के कार्यकर्ताओं एवं सदस्यों ने सैकड़ों जड़ी-बूटियां एवं औषधीय पौधों का वितरण एवं

रोपण किया। यज्ञ में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और यज्ञ के माध्यम से औषधीय पौधों की महता पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर संगठन के जिला प्रभारी सुनील कुबड़े, बिमल दुबे, प्रीति साहू और रामदयाल बोरबन ने उपस्थित होकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री उईके ने हरियाली अमावस्या पर हरिशंकरी का किया रोपण

बैतूल-- केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद दुर्गादास उईके ने कहा कि आज हम मंगल पर जीवन खोजने की ओर अग्रसर हैं, किंतु हमें इस बात पर अधिक ध्यान देना होगा कि हमारे जीवन में मंगल है या नहीं। धरती पर जितने अधिक वृक्ष रहेंगे, उतना ही अधिक वातावरण संतुलित रहेगा और चारों ओर मंगल ही मंगल होगा। केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री उईके रविवार को भारत भारती आवासीय विद्यालय में हरियाली अमावस्या के अवसर पर आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय राज्य मंत्री श्री उईके ने भारत भारती विद्यालय परिसर में हरिशंकरी (बरगद, पीपल, पाकड़) का रोपण कर विधिवत पूजन अर्चन की। उन्होंने कहा कि



सनातन संस्कृति मान्यताओं में मत्स्य पुराण के अनुसार पीपल को भगवान हरी विष्णु, बरगद को भगवान श्री शंकर तथा पाकड़ को भगवान श्री ब्रह्मा का स्वरूप माना

गया है। इस अवसर पर वरिष्ठ पर्यावरण विद मोहन नागर, प्राचार्य जितेन्द्र परसाई, प्रधानाचार्य वैभव जोशी सहित अन्य पर्यावरण प्रेमी उपस्थित थे।

पुलिस ने दो युवकों से पिस्टल और कारतूस किए बरामद



बैतूल। सारणी थाना पुलिस ने दो युवकों को पिस्टल और कारतूस के साथ गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार ने बताया कि 3 अगस्त को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि ड्रिलिंग कैप पाथाखेड़ा के पास जंगल में बने खंडहर के पास दो सदिध व्यक्ति पिस्टल बेचने की

फिराक में हैं। सूचना प्राप्त होने पर थाना सारणी पुलिस व चौकी पुलिस की संयुक्त टीम के मुखवीर द्वारा बताया स्थान से दो सदिध व्यक्ति को पकड़ा जिनसे अपना नाम पता पूछने पर अपना नाम आशीष पवार पिता सतेन्द्र पवार उम्र 26 साल निवासी ग्राम रतनपुर थाना बैतूल बाजार जिला

शिव मंदिर विनोबा नगर में भगवान श्री गणेश व रिद्धि सिद्धि का विवाह प्रसंग का किया वर्णन

बैतूल एवं प्रियांशु चक्रवान पिता पप्पू चक्रवान, 18 साल निवासी ग्राम धसेड थाना सारणी का होना बताया। स्टाफ की मदद से चेक करने पर आशीष पवार के कब्जे से एक पिस्टल एवं प्रियांशु चक्रवान के कब्जे से एक जिंदा कारतूस मिला। पिस्टल एवं कारतूस की कीमती करीबन 4000 रुपये है। उक्त कार्याही में एसडीओपी सारणी रोशन जैन के निर्देशन में गठित टीम व थाना प्रभारी सारणी निरी. अरविंद कुमार के मार्गदर्शन में चौकी प्रभारी पाथाखेड़ा जिन वंशज श्रीवास्तव, सर्जन शिवपाल सिंह इरापचे, प्र० आर 333 आसिफ खान, प्र०आर० एकांनद, आर० 285 रवि मोहन, आर० 388 राजू बरकडे, सैनिक 296 विनोद की सहायनीय भूमिका रही।

बैतूल।

श्री शिव मंदिर विनोबा नगर बैतूल में सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव समारोह एवं पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। शनिवार को भगवान श्री गणेश गणेश का जन्म एवं श्री गणेश के साथ रिद्धि सिद्धि के विवाह प्रसंग का आयोजन किया गया। कथावाचक पंडित नरेंद्र दुबे ने श्री शिव महापुराण कथा सुनाते हुए कहा कि संतान गणपति स्तोत्र के जाप से संतान का व्यक्तित्व तेजस्वी बनता है और समाज में मान सम्मान बढ़ता है। चतुर्थी के दिन रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान श्री गणेश की पूजा करने से धन की कमी नहीं होती। कथावाचक पंडित नरेंद्र दुबे ने कहा कि हिंदू धर्म में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और सर्वशक्तिमान माना जाता है, मान्यता है कि गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि आती है, सभी परेशानी दूर होती है बुद्धि, समृद्धि, धन, वैभव के साथ आत्मा शुद्ध होती है एवं दरिद्रता का नाश होता है। किसी भी शुभ काम या मांगलिक कार्य में गणेश जी की पूजा का विधान है। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा अर्चना और उपासना करने से गणपति बप्पा सुखी जीवन का आशीर्वाद देते हैं। कथावाचक पंडित नरेंद्र दुबे ने कहा कि श्री गणेश जी की पूजा सभी देवी देवताओं की पूजा से पहले की जाती है।



भगवान श्री गणेश को अगर अपनी ताकत बनाना है तो लाल गुड़हल का फूल उनके सिर पर चढ़ाये और उसे सुखाकर अपने अपने पर्स में रखने से धन की कमी नहीं होती। संतान प्राप्ति के लिए संतान गणपति स्तोत्र का जाप कर सकते हैं इस स्तोत्र का पाठ किसी भी मंगलवार से शुरू किया जा सकता है और संतान प्राप्ति का संकल्प लेकर इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इस स्तोत्र के जाप करने से संतान प्राप्ति में आने वाली बड़ाएं दूर होती है और भगवान गणेश जी की कृपा प्राप्त



होती है। भगवान श्री गणेश की उपासना से उपासक को संतान प्राप्ति के साथ-साथ सुख शांति मिलती है संतान गणपति स्तोत्र के निरंतर जाप से संतान बलशाली निडर और ज्ञानवान बनती है।

आज होगा सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण महोत्सव एवं पार्थिव शिवलिंग पूजन का समारोह---

आयोजन समिति के गोपाल साहू एवं अजय जीतपुरे ने बताया कि सात दिवसीय संगीतमय श्री शिव महापुराण कथा महोत्सव

एवं पार्थिव शिवलिंग पूजन अनुष्ठान समारोह का समापन 4 अगस्त दिन रविवार को किया जाएगा। रविवार को सुबह 9 बजे हवन पूजन एवं अनुष्ठान समारोह एवं 11 बजे से पार्थिव शिवलिंग पूजन एवं 12 बजे से श्री शिव महापुराण कथा कथा में द्वादश ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाई जाएगी एवं कथा का समापन किया जाएगा साथ ही शाम को 6 बजे से भंडारा प्रसादी वितरण करने का कार्य किया जाएगा जिले वासियों से इस अवसर पर उपस्थित रहने का आग्रह किया गया है।

पूरी बरसात जैसे चल रहे है वैसे ही बगैर चूं चपड़ के चलना भी ऐतिहासिक मजबूरी है...

नर्मदापुरम। आज ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पहुंच मार्ग की व्यथा लिखकर सुरेन्द्र सिंह अरोरा जो एक जाने माने पत्रकार हैं उन्होंने पहली बार महसूस कराया हां तकलीफ उन्हें भी होती है। जिले भर के तमाम बड़े, छोटे, मझौले अधिकारी कर्मचारियों से अरोरा साहब से सबकी जमकर छनती है। मजाल उनके रडार से कोई खबर स्लिप कर जाएँ.. सबको साथ लेकर चलने वाले अरोरा साहब ने जब तकलीफ लिखी है तो निश्चित मानों कोई बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर लिखी गई पीड़ा का जिक्र कुछ इस तरह आज सामने आया।

लाखों रुपए की लागत से बिना मापदंड की निर्मित सड़क नर्मदापुरम के मंगलवारा घाट स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब में जाने के लिए आपको ऐसे हालात से गुजरना होगा। जुमेराती काली मंदिर से मंगलवारा घाट तक 2 माह पूर्व बनाई गई सड़क, निर्माण के दौरान भी ठेकेदार को बताया गया था, कुछ स्थानों पर पानी भर जाता है, बावजूद इसके ठेकेदार ने घटिया निर्माण किया। इसके पहले भी लगभग 2 वर्ष पूर्व सड़क का सीमेंटीकरण किया गया था, उस दौरान भी घटिया निर्माण किया गया



पीड़ा लिखकर उसका भुगतान नहीं किया जाए लिख तो दिया लेकिन क्या वास्तव में ठेकेदार का भुगतान रोका जा सकेगा...? यह सवाल सोशल

था, और पानी भरता था। नगर पालिका योग्य अ नु भ व ी ठेकेदारो से काम क्यों नहीं करवाती है। काली मंदिर जुमेराती चौक से मंगलवारा घाट तक नवनिर्मित डामर मार्ग का भुगतान ठेकेदार को न दिया जाए और मार्ग की जांच की जाए। अरोरा साहब ने

मीडिया पर भी उठा महेश चौकसे ने इस मामले में खुलकर लिखा नहीं हुआ है तो हो जायेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परिषद का गठन ही पार्श्वों के साथ गठबंधन के हुआ है।श्रीमती नैना सोनी नपाध्यक्ष पद की दावेदार थी। पूर्व विधायक गिरजा शंकर शर्मा के बहुत करीबी गोटू सोनी की धर्म पत्नी को नपाध्यक्ष इसलिए नहीं बनाया गया कि पूर्व सांसद और गिरजा शंकर शर्मा के पुत्र के व्यवसाई पार्टनर महेंद्र यादव को विधायक जी ने समर्थन देकर पार्श्वों को और ज्यादा उपकृत करा दिया। इससे सभी पार्श्व खुश हैं और उनकी बोलती बंद है। फिर पार्श्व अब खुद अपने पड़ों के माध्यम से ठेकेदारी कर रहे हैं। ऐसे में मजाल नपाधिकारी कि जो बिल भुगतान नहीं करे। बात महेश चौकसे बाखूब जानते हैं इसलिए उन्होंने सुरेन्द्र सिंह की बात काटते हुए लिख डाला भुगतान नहीं हुआ है तो हो जायेगा। बस हमें तो पूरी बरसात जैसे चल रहे हैं वैसे ही बगैर चूं चपड़ के चलना है। फिर दुर्भाग्य इस नगर का यह भी है कि जब तक विधायक नहीं चाहेंगे नगर का भत्ता नहीं हो सकेगा चाहे जिसे जो करना है करें।

पत्रकार पर जानलेवा

हमला मामला दर्ज

नरसिंहपुर। जिले में अवैध कार्य करने वालों से जहां आमजन परेशान रहते हैं वहीं इनके खिलाफ समाचार प्रकाशित करने वाले पत्रकारों को भी परेशान किया जाता है। इसी श्रृंखला में करेली थाना अंतर्गत आमगांव में पत्रकार ब्रजेश दीक्षित के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। उनके साथ अभद्रता कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी गई। जिसकी रिपोर्ट थाना करेली में ब्रजेश दीक्षित के साथ सुरजीत सिसौदिया ने की है। इस घटना को लेकर जिले के पत्रकारों में रोष है। जिला मुख्यालय के पत्रकारों ने रविवार को नरसिंहपुर आए प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री नरेन्द्र शिवाजी पटेल को जापन सौंपा। जापन में उल्लेख किया गया है कि उक्त घटना के आरोपी जुआ-सट्टा खिलाते हैं इनके कारण आमगांव बड़ा क्षेत्र में अप्रिय घटना होती है। राज्यमंत्री श्री पटेल ने पुलिस अधीक्षक से दूभाष पर चर्चा कर दीर्घियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है।

पलकमती नदी की हवाएं

हीरालाल गोलानी सोहागपुर

प्रदेश में विधानसभा का कलर दूसरा होता

विगत दिनों एक राजनैतिक सोशल मीडिया पर सबसे पहले भाजपा का झंडा थामने एवं भाजपा के संस्थापक सदस्य के परिवार के प्रति अर्नगल टिप्पणियां की गई।यह क्षेत्र की जनता-जनार्दन जानती है कि सोहागपुर ब्लाक में भाजपा का वट वृक्ष किसने लगाया था। उसकी छाया अब कौन कौन ले रहे हैं। कैसे कैसे लोग ले रहे हैं किसी की आंखों से छिपा नहीं। लेकिन यदि उस परिवार का एक सदस्य भी ग्रामीण क्षेत्रों में विधानसभा 2023 के चुनाव में चल गया होता तो मध्यप्रदेश के नक्शे में सोहागपुर विधानसभा का कलर दूसरा होता।

निंदक नियारे रखिए

कबीर दास जी के दोहे जीवन के हर पहलू पर लिखे गए हैं। निंदक नियारे रखिए आंगन कुटी छवाय, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाय। उनका ये दोहा मनुष्य को अपने पास सिर्फ चापलूसी वाले व्यक्ति को ही न रखकर निंदा करने वाले लोगों को रखना चाहिए। कबीरदास जी का मक़सद यह था। कि सही यथार्थ सशक्त मार्गदर्शन मिले। जिससे जनता-जनार्दन को लाभ मिलता रहे।हुज़ूर यदि चापलूसों की विधानसभा चुनाव की हिस्ट्री निकलवा ले। तो दूध का दूध, पानी पानी हो जाएगा?।

अंत में

2023 के विधानसभा चुनाव में ग्राम गुजर खेरी में एक भाजपा समर्पित नवधनाद्वैता जो निस्वार्थ से विधायक की विजयश्री कराने में लगे हुए थे।जो वहां गति हुई थी। उसकी क्षेत्र में चर्चा भी खूब रही थी। लेकिन ओर गति होने से कैसे बची? यह अन्दर खाने की बात है।कि उनके साथ गए एक भाजपा के कार्यकर्ता का जब कांग्रेसियों को पता चला तब उन्होंने आनन-फ़ानन में कार की चाबी वापिस करवाई थी। अब लगाइए कयास ?

ट्रक और कमांडर वाहन की भिड़ंत, 2 महिलाओं की मौत,7 घायल

मजदूरी कर घर लौट रही थी, धारना गांव के पास हुआ हादसा



सिवनी (नप्र)। सिवनी जिले में शनिवार रात को ट्रक और कमांडर वाहन की भिड़ंत हो गई। हादसा बरघाट थाना क्षेत्र के धारना गांव के पास रात करीब 8 बजे हुआ जिसमें दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 7 महिलाएं घायल हो गईं। जिन्हें एंबुलेंस की मदद से जिला हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां महिलाओं की हालत स्थिर है।

बरघाट थाना प्रभारी मोहनीस बेस ने बताया कि शनिवार को महिलाएं बेहरई गांव के पास खेत में धान का रोपा लगाने गई थी। वहां से रात को कमांडर वाहन में सवार होकर अपने घर वापस जा रही थी। इसी बीच धारना के पास ट्रक के साथ कमांडर की जोरदार भिड़ंत हो गई।हादसे में जीरन बाई पति बालचंद और केशर बाई पति हरिश्चन्द्र की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 7 अन्य महिलाएं घायल हो गईं जिन्हें बरघाट अस्पताल में उपचार के बाद जिला अस्पताल लाया गया जहां उनकी हालत में सुधार है। वहीं पुलिस दो महिलाओं के शव को पीएम के लिए भेजकर हादसे की जांच कर रही है।

म.प्र. देश की समृद्ध खनिज संपदा और औद्योगिक विकास का प्रतीक

मुख्यमंत्री डॉ. यादव बैंगलुरु इन्वेस्ट मीट में उद्योगपतियों को खनिज क्षेत्र में निवेश के लिये करेंगे प्रोत्साहित

भोपाल(नप्र)। मध्यप्रदेश भारत के खनन और खनिज क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता को लगातार साबित कर रहा है, जिससे उल्लेखनीय उपलब्धियाँ और भविष्य की संभावनाएँ सामने आ रही हैं, जो महत्वपूर्ण औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को प्रोत्साहित करेंगी। इसी के मद्देनजर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव दो दिवसीय प्रवास पर बैंगलुरु जाने वाले हैं। जहाँ वे 8 अगस्त को इंटरैक्टिव सेशन में प्रदेश में उपलब्ध खनिज संपदा पर उद्योगपतियों का ध्यान आकर्षित कर निवेश के लिये प्रोत्साहित करेंगे। गौर तलब है कि मिनरल ऑप्शन के लिये मध्यप्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहला पुरस्कार भी मिल चुका है।

मध्यप्रदेश में जल्दी ही एल्युमिनियम, लेटराइट, बॉक्साइट, मेटल, डायमंड, गोल्ड, लाइमस्टोन मैंगनीज के 33 ब्लॉक की नीलामी होने जा रही है। इसी प्रकार 17 कोल ब्लॉक के ऑक्शन भी प्रक्रिया में है। प्रमुख खनिजों के 20 ब्लॉक ऑक्शन की प्रक्रिया में है। इनमें मैंगनीज, डायमंड बॉक्साइट, लेटराइट, गोल्ड, बेस मेटल और लाइमस्टोन हैं। इस दृष्टि से मध्यप्रदेश में खनिज संपदा में निवेश की बहुत ज्यादा संभावना बनी हैं। पिछले साल एक साथ 51 ब्लॉक का आव्हान हुआ था, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है।

मध्यप्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज संसाधनों में कोयला, लाइमस्टोन, डायमंड और पायरोफ्लाइट है। मध्यप्रदेश देश का चौथा सबसे बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। यहां सिंगरीली, सीधी, छिंदवाड़ा, बैतूल, शहडोल, अनूपपुर, उमरिया और नरसिंहपुर भरपूर कोयला भंडार है। कोयले का उपयोग थर्मल पावर प्लांट्स और कोल गैसीफिकेशन प्लांट्स में होता है। इनसे संबंधित उद्योगों के लिए निवेश की भरपूर संभावनाएँ हैं।

इसी प्रकार चूना पत्थर का भी प्रदेश में भरपूर भंडार है। यहां रीवा, सतना, सीधी, मैहर, दमोह, कटनी पन्ना, धार और नीमच में भरपूर भंडार है। देश के कुल लाइमस्टोन भंडार का 9ब मध्यप्रदेश में है। इस दृष्टि से सीमेंट उद्योग के लिए मध्यप्रदेश एक आदर्श निवेश स्थान है। यहां जो लॉजिस्टिक क्षेत्र में सुधार हुआ है इस दृष्टि से भी मध्यप्रदेश से देश के सभी राज्यों का संपर्क बेहतर हो गया है।

देश में उपलब्ध डायमंड भंडार का 90 प्रतिशत मध्यप्रदेश में पाया जाता है। यह अकेले पन्ना और छतरपुर में है। इस दृष्टि से यहां डायमंड बिजनेस पार्क और और कंपोजिट लाइसेंस के लिए 5 ब्लॉक की पहचान की गई है।

मध्यप्रदेश पायरोफ्लाइट के उत्पादन में भी अग्रणी राज्य है। यहां देश के उत्पादन का 41 प्रतिशत उत्पादन हो रहा है। देश में सर्वाधिक भंडार 14 मिलियन टन मध्यप्रदेश में है, जो छतरपुर, शिवपुरी और टीकमगढ़ में है।

जंबाडा रोड पर गिरा पेड़ पांच घंटे से भी ज्यादा समय तक रहा रास्ता बंद बिजली गुल, बेबस रहा प्रशासन

लगातार बारिश से कई गांवों का संपर्क टूटा



आमला। बीते कई दिनों से इलाके में हो रही लगातार बारिश के चलते रविवार को जंबाडा रोड दिनभर प्रभावित रहा, यहां मंगल भवन के पास एक विशालकाय पुराना पेड़ गिरने से दोनों तरफ का आवागमन कई घंटे तक बंद रहा तो वहीं देवागांव नदी पर चंद्रभागा नदी के पुल पर बहने से कई घंटे तक कई गांवो का संपर्क टूट गया था।

रविवार सुबह लगातार ही रही बारिश के चलते जंबाडा रोड पर चंद्रभागा नदी के पुल के ऊपर बहने से देवागांव, कनौजिया,जंबाडा, सोनतलाई, लालवाड़ी आदि कई गांवो का दिन भर आमला से संपर्क कटा रहा।

यही आमला के मंगल भवन क्षेत्र में एक विशालकाय पुराना पेड़ सड़क पर गिरने से कई घंटे तक आवागमन बाधित रहा, आमला जंबाडा रोड एक व्यस्ततम मार्ग है, संयोगवश जिस समय पेड़ गिरा उस समय

यहां कोई आवागमन नहीं था अन्यथा बड़ा नुकसान हो सकता था, जानकारी के मुताबिक शहर के सभी मुख्य सड़कों के किनारे पर इसी तरह के कई पुराने पेड़ लगे हैं जो कभी भी दुर्घटना का सबब बन सकते हैं।

प्रशासन दिखा बेबस बारिश के पूर्व नहीं की कोई तैयारी

रविवार को शहर में जंबाडा रोड पर गिरे पेड़ को हटाने में ही स्थानीय प्रशासन को कई घंटे का समय लग गया देखा गया है कि पेड़ को हटाने में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने आसपास के कुछ लोगों को पेड़ काटने के लिए कहा जो कई घंटे तक कुल्हाड़ी से पेड़ काटते रहे, जिससे आवागमन बाधित रहा, यहां प्रशासन की बेबसी साफ-साफ नजर आ रही है जिस पर लोग काफी नाराज भी

दिखाई दिए, लोगों का कहना है कि इस मौके पर प्रशासन को जेसीबी आदि की मदद लेना चाहिए था, किंतु इतनी बड़ी घटना के बाद भी प्रशासन स्थानीय लोगों की मदद से कुल्हाड़ी से पेड़ कटवाता रहा, जिसमें कई घंटे बीत गए,और लोग परेशान होते रहे, इस घटना से स्थानीय प्रशासन की नाकामी साफ-साफ दिखाई पड़ रही थी, लोगों का कहना है की बारिश के पूर्व स्थानीय प्रशासन को जो तैयारी करना था वैसी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही है, तो वहीं स्थानीय लोग प्रशासन को कई बार शहर के कई खतरनाक होते पेड़ों के बारे में जानकारी दे चुके हैं, जो कभी भी बारिश के मौसम में गिर सकते हैं और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती है, इसके लिए लोग लगातार प्रशासन को बताते हैं, किन्तु कोई कार्यवाही नहीं की जाती है, ऐसे में शहर में कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

गाडरवारा से मूंग भरा ट्रक बकतरा डेम पर मिला था खाली

नगर निरीक्षक कंचनसिंह के नेतृत्व में

सोहागपुर पुलिस को मूंग लूटने के सनसनीखेज मामले का पर्दाफाश किया

हीरालाल गोलानी सोहागपुर। पुलिस अधीक्षक डॉ गुरकरणसिंह एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आशुतोष मिश्र के निर्देशन में, एसडीओ पुलिस संजू चौहान के मार्गदर्शन में नगर निरीक्षक कंचनसिंह के नेतृत्व में सोहागपुर पुलिस ने गाडरवारा जिला नरसिंहपुर से मूंग से भरे ट्रक मूंग लूटने वाले सनसनीखेज मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है।

नगर निरीक्षक कंचनसिंह ने बताया कि 01 अगस्त 24 को फरियादी सुरेशकुमार साहू पिता लालजीप्रसाद साहू निवासी ग्राम कामती थाना गाडरवारा जिला नरसिंहपुर ने सोहागपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 26 सितंबर 24 को मेरा ग्रेडेड मूंग करीब 21 टन को नव भारत ट्रांसपोर्ट सर्विस इंदौर के ट्रक क्र. एम पी 09 एच एच 1040 में देर रात करीब 11.30 बजे तक लोड करके ट्रक माल सहित मय ड्रायवर व हेल्वर के इंदौर रवाना किया था । 27 सितंबर.24 को ट्रक में जीपीएस के माध्यम से पता चला की ट्रक गलत दिशा में बकतरा जिला रायसेन की तरफ गया है। इसके साथ ड्राइवर का फोन बंद आ रहा था।शंका होने पर फरियादी सुरेशकुमार अपने साथियों के साथ जीपीएस के माध्यम से ट्रक की तलाश में बाड़ी बकतरा की तरफ पहुंचा। ग्राम बाड़ी से आगे डेम के पास उक्त ट्रक रोड़ किनारे खड़ा दिखा। पीछे से चैक किया गया तो ट्रक खाली था। ड्राइवर एवं हेल्वर की नहीं थे। बाद में फरियादी ने ड्राइवर



एवं हेल्वर की तलाश की गई। केमबाली के आगे ड्राइवर एवं हेल्वर फरियादी को मिले। उन्होंने घटना के संबंध में बताया कि 27 सितंबर.24 को एक स्वीफ्ट कार में सवार 4 लोगों के द्वारा ट्रक के सामने गाड़ी खड़ी कर ड्रायवर व हेल्वर को गाड़ी से जबरदस्ती उतारकर मूंग से भरा ट्रक को लूटकर बाड़ी बकतरा तरफ ले गए । तथा ड्राइवर एवं हेल्वर को स्वीफ्ट गाड़ी में बैठाकर केमबाली के आगे सुनसान सड़क पर डरा धमकाकर छोड़कर ड्राइवर का मोबाईल भी छीन लिया। फरियादी के थाना उपस्थित होकर घटना के संबंध में जानकारी दी। मामला लूट का पाया जाने पर मामले में अपराध क्र. 446,24 धारा 309 (4) बीएनएस का आरोपीगण अंकित पटेल, राम कुमार गुर्जर, अभिषेक पलिया उर्फ पलिया एवं रितेश केवट उर्फ रामदेव सभी निवासी पिपरिया के विरुद्ध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

पुलिस टीम बनाई –मामले में तत्काल वरिष्ठ

अधिकारियों से आवश्यक निर्देश प्राप्त कर आरोपियों की व लूटे गये माल की तलाश करने के लिए अलग अलग स्थानों पर टीम बनाकर पुलिस बल रवाना किया गया। मामले में मुख्य आरोपी अभिषेक पुर्विया उर्फ पलिया पिता अशोक पुर्विया उम्र 20 साल निवासी पिपरिया को मंडी टोला के पास पिपरिया से एवं रितेश केवट उर्फ रामदेव पिता स्व. पप्पू केवट उम्र 19 साल निवासी पिपरिया को तिलक वार्ड पिपरिया से विधिवत गिरफ्तार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। उनसे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई। पूछताछ में उन्होंने बताया कि अंकित एवं रामकुमार गुर्जर के कहने पर घटना कारित करना बताया गया। तथा घटना में लूटे हुये मूंग ट्रक को बकतरा के पास अन्य ट्रैक्टर ट्राली में खाली करना बताया गया। तथा ट्रक को लावारिश हालात में बाड़ी से आगे डेम के पास खड़ा करना बताया गया।

लूटी गई गिरेड मूंग करीबन 21टन की कीमत करीबन 15लाख से अधिक की बताई जाती है।

महती भूमिका सोहागपुर थाने की

नगर निरीक्षक कंचनसिंह, उनि प्रवीण यादव, सजनि अशोक सातनकर, प्रधान आरक्षक प्रकाशसिंह राजपूत, आरक्षक दिनेश धुर्वे, आरक्षक नरेन्द्र पटेल, आरक्षक. बलराम सोदे, महिला आरक्षक स्वाती राजपूत,

पिपरिया थाने का सहयोग

आरक्षक राममोहन रजक, आरक्षक अफसर खान, आरक्षक नीतेश दवडे, आरक्षक रामेश्वर उइके, सायबर सेल के आरक्षक दीपेश सोलंकी, अभिषेक नरवरिया की भी आरोपियों की तलाश पतारसी तथा गिरफ्तारी में सहयोग रहा।

